वर्ष : 16 ❖ अंक : 327 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
रविवार, 10 जुलाई 2022

पीएम मोदी ने जनता का दम निकाल दिया है : राहुल 3

लोगों को बांटने का हथियार नहीं हो सकता धर्म : सीएम स्टालिन 8

फिर डरा रहा कोरोना, 59 नए मामले

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 09 जुलाई । हिमालयी राज्य सिक्किम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 59 नये मामले सामने आये हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 39401 हो गयी है।

शनिवार को जारी बुलेटिन के अनुसार इस दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है जिससे मृतकों की संख्या 457 हो गयी है। वर्तमान में सिक्किम में कोविड के 146 सक्रिय मामले हैं और 38036 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं 762 लोग दूसरे राज्यों में गये हैं।

जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में जांचे गये कुल 247 नमूनों में से पूर्व जिले में ही 37 नये मामले दर्ज किये गये हैं। वहीं दक्षिण सिक्किम में 12, पश्चिम सिक्किम में 6 और उत्तर सिक्किम में 4 मामले मिले हैं। राज्य में अभी तक कुल 343314 नमूनों की जांच की जा चुकी है।

चामलिंग के नेतृत्व का इंतजार कर रही है जनता : एम.के. सुब्बा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 09 जुलाई । आज इंदिरा बाईपास स्थित पार्टी मुख्यालय के सम्मेलन हॉल में उत्तर जिला और गंगटोक और पाकिम जिलों के युवा मोर्चा की समन्वय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के युवा मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता एम.के. सुब्बा ने की। इस सभा में उत्तर जिले और गंगटोक और पाकिम जिले के युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह जानकारी एसडीएफ के प्रचार प्रसार महासचिव विष्णु दुलाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में मौजूद युवाओं ने एसडीएफ पार्टी को मजबूत करने के पक्ष में अपने विचार व सुझाव रखे। साथ ही आज की बैठक में एसडीएफ पार्टी में युवाओं के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। युवाओं ने पवन चामलिंग के नेतृत्व पर भरोसा जताया। आज की बैठक में युवाओं के लिए चिंतन शिविर आयोजित करने, पाकिम जिले में पार्टी कार्यालय स्थापित करने, युवाओं को डिजिटल मीडिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और युवाओं को पार्टी संगठन के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बड़े निर्णय लिए गए।

अपने अध्यक्षीय भाषण में एम. के. सुब्बा ने युवाओं के विभिन्न विचारों और सुझावों का स्वागत किया। इसी तरह अपने संक्षिप्त संबोधन में उन्होंने कहा कि एसडीएफ पार्टी में युवाओं की सभी समस्याओं का समय से समाधान किया जाएगा। एम.के. सुब्बा ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में, वर्तमान सरकार ने एसडीएफ पार्टी को समाप्त करने का पूरी कोशिश की। एम.के. सुब्बा ने कहा कि एसडीएफ पार्टी पिछले तीन वर्षों से राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है और जन-समर्थक मुद्दों पर लोगों की आवाज उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि सिक्किम की जनता पवन चामलिंग और एसडीएफ पार्टी के दूरदर्शी नेतृत्व का पूरे विश्वास के साथ इंतजार कर रही है।

उन्होंने बताया कि पार्टी ने सामूहिक कार्यकारिणी समिति के माध्यम से एसडीएफ पार्टी संगठन के विस्तार को जमीनी स्तर पर अधिक सक्रिय और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने युवाओं

से सिक्किम और सिक्किम के लोगों के सुरक्षित जीवन और अस्तित्व के लिए एसडीएफ पार्टी में सकारात्मक होकर काम करने का युवाओं से आग्रह किया।

बैठक को पार्टी की युवा प्रकोष्ठ के डॉ. मिचुंग भूटिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उगेन नेदुप भूटिया और सोशल मीडिया के उपाध्यक्ष बराप नामग्याल भूटिया ने भी संबोधित किया। बैठक में पूर्व जिला उपाध्यक्ष कर्मा ताशी भूटिया ने आभार व्यक्त किया। छिरिंग वांग्दी लेप्चा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर जिला, देव गुरुंग, उपाध्यक्ष, प्रशासनिक मामले, एलएम भट्टाराई, पूर्व जिला उपाध्यक्ष आज की बैठक में उपस्थित थे।

एसकेएम व बीजेपी सिलीगुड़ी में द्रौपदी मुर्मू का करेगी स्वागत

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 09 जुलाई । राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का एसकेएम और राज्य के भाजपा सांसदों से मिलने के लिए शनिवार को सिक्किम का दौरा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के राजनीतिक सचिव जैकब खालिंग ने पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी।

ज्ञात हो कि द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों से समर्थन लेने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के वरिष्ठ नेता जैकब खालिंग ने संवाददाताओं से कहा, शिंजो आबे के सम्मान में भारत में मनाए जा रहे शोक को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू की सिक्किम यात्रा स्थगित कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ एसकेएम और सिक्किम के भाजपा

नेताओं ने आगामी राष्ट्रपति चुनावों में उनकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगने के लिए द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए सभी इंतजाम किए थे, लेकिन हमें पता चला कि उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने एसकेएम और भाजपा के विधायकों के साथ एक सप्ताह पहले राष्ट्रीय राजधानी में मुर्मू से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें अपना समर्थन देने का वादा किया था।

मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव विकास बस्नेत ने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम और कनेक्टिविटी के मुद्दे के कारण हम 11 जुलाई को एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए सिलीगुड़ी में एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जहां हम सिक्किम की संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करेंगे।

ज्ञात हो कि 32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभा में एनडीए के 31 सदस्य हैं, जिसमें सत्तारूढ़ एसकेएम के 19 और भाजपा के 12 सदस्य शामिल हैं जो बाहर से तमांग सरकार का समर्थन करते हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के एकमात्र विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने भी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है।

राज्य सरकार पैदा कर रही है डर का माहौल : गोपाल छेत्री

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 09 जुलाई । सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने राज्य सरकार द्वारा राजधानी गंगटोक में 9 से 12 जुलाई तक निषेधाज्ञा जारी करने को लेकर सवाल खड़े किये हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे सस्ते रूप में कानून का दुरुपयोग कर बगैर किसी कारण के ही लागू कर राज्य की सामान्य व शांतिपूर्ण स्थिति को नष्ट कर आतंक फैलाने वाला कदम करार देते हुए इसकी निंदा की है।

सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल छेत्री ने इस सम्बंध में एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वर्तमान में गंगटोक में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य एवं सुचारू है और किसी प्रकार की अशांतिपूर्ण घटना नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया है? उनके अनुसार इससे राज्य सरकार की कायरता एवं कमजोरी जाहिर हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के मुख्य सचिव सुरेश चन्द्र गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सबूत रहने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इसके कारण आम जनता में विरोध पनप रहा है। राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने के दावे के साथ सत्ता में आयी एसकेएम सरकार एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ कदम उठाने में पूरी तरह विफल रही है।

छेत्री ने आगे कहा कि राज्य के मुख्य सचिव ने सिक्किम समाज और सरकारी स्तर पर छल कर भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके पुख्ता प्रमाण होने पर भी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रवक्ता उन्हें बचाने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के नागरिक समाज, विभिन्न पार्टियों तथा संघ-संस्थाओं द्वारा आरोपी एससी गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि इस संदर्भ में हाल ही में एक संयुक्त जांच कमिटी का गठन किया गया है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करने के बाद सरकार एवं प्रशासन के कायराना हरकत के कारण जनता विरोधी एवं भ्रष्टाचारी की सहयोगी बन गयी है। ऐसे में यहां 144 धारा लागू करने के स्थान पर संविधान की धारा 356 लागू करनी चाहिये।

कांग्रेस पार्टी ने विज्ञप्ति में कहा कि जनता की आवाज न सुनने वाले

एवं भ्रष्टाचारी को पालने वाली सरकार सिक्किम की जनता को नहीं चाहिये। पार्टी अनावश्यक रूप से धारा 144 लागू कर राज्य में आतंक फैलाने वाली ऐसी लाचार व डरपोक सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करती है। साथ ही नेपाली आदि कवि भानु भक्त की जन्म जयंती के अवसर पर इस प्रकार धारा 144 लागू कर सरकार ने नेपाली जाति के उत्सव के खिलाफ भी कदम उठाया है। पार्टी ने इसके साथ ही इस मसले पर राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। साथ ही इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट पार्टी आलाकमान एवं केंद्र सरकार के सभी सम्बंधित विभागों को भी भेजी गयी है।

भानु जयंती को लेकर अंतिम चरण की समीक्षा बैठक सम्पन्न

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 09 जुलाई । नेपाली साहित्य परिषद, सिक्किम के तत्वावधान में आयोजित होने वाले 208वें भानु जयंती समारोह को लेकर आज समारोह समिति के अध्यक्ष बीएस पंथ की अध्यक्षता में अंतिम चरण की समीक्षा बैठक परिषद सभागार में आयोजित की गयी। इस दौरान समारोह को सफल बनाने हेतु विभिन्न उप-समितियों से कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त की गयी और उन पर संतोष जताया गया। वहीं परिषद अध्यक्ष ने समारोह को सफल बनाने हेतु उपस्थित लोगों को एकजुट होकर पूरी मेहनत के साथ इसके आयोजन हेतु सुझाव दिये।

वहीं बैठक में आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाले 208वें भानू जयंती समारोह के आयोजन के पहले निर्धारित कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के विषय में भी विचार व्यक्त किये गये।

इसी बीच समारोह समिति द्वारा आज से शुरू किये गये अंतर विद्यालय एवं खुली पाठ प्रतियोगिता में कुल 16 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसमें सिच्छे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पासांग छिरिंग तमांग ने प्रथम, ताशी नामग्याल अकादमी की छात्रा सुश्री तिमाशा गौतम ने द्वितीय और मॉडर्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सुश्री आशना कार्की ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

इसके अलावा खुली पाठ प्रतियोगिता में कृष्ण ढंगले प्रथम, गोपाल पाठक द्वितीय और नीलम गुरुंग तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिक्किम अकादमी के सचिव पीएल शर्मा ने की। श्रीमती मणिका शर्मा द्वारा संचालित उक्त प्रतियोगिता में स्वागत भाषण नेसाप उपाध्यक्ष हरि ढुंगेल और धन्यवाद ज्ञापन सुश्री लुइस बिष्ट ने रखा।

ट्राउट मछली पालन में उदाहरण बने सुभाष राई

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 09 जुलाई । सिक्किम में वर्तमान में ट्राउट मछली पालन एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ है। इसे अपना कर काफी सारे लोग लाभान्वित हुए हैं और मछली बेच कर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। इसमें पाकिम जिला के छुजाचेन स्थित उत्तर रेगु के एक किसान सुभाष राई भी है जो शौकिया ट्राउट मछली पालन से शुरू कर आज राज्य के सर्वश्रेष्ठ ट्राउट मछली उत्पादक बन चुके हैं।

सुभाष राई ने बताया कि अपने पड़ोस में रहने वाले तथा शौकिया तौर पर ट्राउट मछली पालन करने वाले एक सरकारी कर्मचारी से प्रोत्साहित होकर उन्होंने मछली पालन आरम्भ करने का मन बनाया था। उसके बाद वह राज्य सरकार के मत्स्य निदेशालय गये और इसके बारे में सूचनाएं प्राप्त कीं। उसके बाद उन्हें बीज-चारे की खरीद तथा रेसवे के निर्माण हेतु सरकारी सब्सिडी भी मिल गयी।

उल्लेखनीय है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में सरकारी योजना को 2016-17 में शुरू की गई थी। उसके बाद 2018 में लाभान्वितों को बीज-चारे एवं रेसवे निर्माण के लिए सब्सिडी देने की शुरुआत हुई। राई के अनुसार शुरू में उनके काफी सारे मछली के चारे की मौत हो गयी। लेकिन वह पूरी मेहनत एवं प्रतिबद्धता के साथ इस व्यवसाय से जुड़ गये और मछलियों की देखरेख एवं अन्य कार्य करने लगे। इस कार्य में निदेशालय की ओर से भी उन्हें पूरा सहयोग तथा तकनीकी जानकारियां प्रदान की गयीं। उनकी मेहनत रंग लायी और 2019 में उन्होंने पहली बार अपनी उत्पादित मछलियां को बेचना आरम्भ किया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा।

पिछले वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित हुए फिश मेले में वह सर्वाधिक 'रैनबो ट्राउट विक्रेता' बने और मुख्यमंत्री मत्स्य उत्पादन योजना के तहत पूर्व

जिला के सर्वश्रेष्ठ मछली उत्पादक चुने गये।

वर्तमान में मछली उत्पादन राज्य में लोगों की आय का स्रोत बन कर उनकी आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इससे जहां आय बढ़ने एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ ही दूर-दराज के इलाकों में पर्यटन की सम्भावनाएं भी तैयार हुई हैं।

कुमुदिनी होम्स की टोली स्विटजरलैंड के लिए रवाना

अनुगामिनी नि.सं.

कालिम्पोंग, 09 जुलाई । स्विटजरलैंड में आयोजित होने जा रहे बेसेल टेटु बैंड डिस्प्ले में भाग लेने के लिए आज कालिम्पोंग से कुमुदिनी होम्स के पाइप एवं ड्रम बैंड के छात्र एवं मेंटर स्टिजरल्यैंड के लिए रवाना हुए। आज कालिम्पोंग के डम्बर चौक में एक शानदार कार्यक्रम में इस टोली को रवाना किया गया।

दरसल सम्पूर्ण भारत देश से पहली दफे स्विटजरलैंड में होने वाले वाले दुनिया के दूसरे बड़े मिलिट्री बैंड डिस्प्ले टेटु में भाग लेने वाला कुमुदिनी होम्स स्कूल भी शामिल है। दरअसल सबसे बड़े टेटु एडिनबर्ग टेटु है। इसमें भाग लेने का सपना लेकर इस दफे स्विटजरलैंड रवाना होने की जानकारी मेंटर प्रियदर्शी लामा ने दिया। वहीं विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भी खुशी प्रकट की। डम्बर चौक में एनसीसी के कैडेट द्वारा जिलाधिकारी आर विमला के हाथों मेंटर प्रियदर्शी लामा को देश का झंडा देकर आज यहां से भेजा गया।

इससे पूर्व आज पद्माभिभूषण जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे एवं मणिपुर भूस्खलन में शहीदों के प्रति मौन धारण किया गया। आज कुमुदिनी होम्स के बैंड को एस्कॉर्ट करने हेतु संत फिलोमिना, प्रणामी बालिका विद्या मंदिर स्कूल एवं मिरिक महकमा से रबीन्द्रनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाइप बेंड आये थे। इस ऐतिहासिक पल को सम्बोधन करते हुई डीएम आर विमला ने सभी को बधाई दी। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्षेत्र और देश का नाम रोशन करने को कहा।

यह टोली कालिम्पोंग पुलिस के सौजन्य से सुकना गेस्ट हाउस में आज रहेंगे तो कल शाम मुंबई के लिए रवाना होंगे।

वहीं सोमवार तड़के यह टोली मुंबई से जर्मनी के म्यूनिक में उतरेंगे और वहां से फिर स्विटजरलैंड के बेसेल में जाकर 11 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। खास बात यह है कि कार्यक्रम में गोरखा सैनिकों का प्रसिद्ध खुकुरी नृत्य भी शामिल है। हालांकि खुकुरी एयरपोर्ट पर ले जाने की अनुमति नहीं होने के कारण स्विटजरलैंड सरकार ने स्थानीय स्तर पर ही खुकुरी तैयार करवाया है।

प्रभावितों को दी गई सरकारी सहायता

प्रीतम लामा

गेजिंग, 09 जुलाई । प्रशासनिक कार्यों को लोगों के घरों तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ जिले के योक्सम महकमा शासक छिरिंग टी भूटिया ने रिम्बिक-टिम्ब्रोंग पंचायत में एकदिवसीय मोबाइल कार्यालय का आयोजन किया। इसमें अंतर्गत आमलोगों के जमीन के पर्चे बनाने, रोजगार कार्ड तैयार करने, विवाह व अविवाहित प्रमाणपत्र देने, आधार कार्ड अपडेट एवं उसकी जांच एवं ऐसे ही कई अन्य प्रशासनिक कार्य किये गये। वहीं इस दौरान महकमा शासक छिरिंग टी भूटिया ने आमलोगों की शिकायतें भी सुनीं और उनके समाधान का आश्वासन दिया।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की इस पहल के अंतर्गत आज लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के क्षतिग्रस्त फसलों, घरों के मुआवजे के चेक भी प्रदान किये गये। वहीं इस दौरान पंचायत के टोपुंग गांव में 2013 में हुए भूस्खलन से क्षतिग्रस्त लोगों को राज्य सरकार द्वारा पुनर्वासन के तौर पर भूमि पर्चा दिया गया। एसडीएम भूटिया ने इस सम्बंध में बताया कि आमलोगों को उनके दरवाजे तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में हम नियमित तौर पर दूर-दराज के क्षेत्रों में 'द्वार पर प्रशासन' पहल का आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार (शेष पृष्ठ ०३ पर)

आतंकवाद पर प्रेस कॉफ्रेंस करने की बजाय, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए : भाजपा

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। आतंकवाद के मसले पर देश के 22 जगहों पर कांग्रेस नेताओं के प्रेस कांफ्रेंस पर कटाक्ष करते हुए भाजपा ने कहा कि तुष्टिकरण के कारण से जिस प्रकार से कांग्रेस ने आतंकवाद का साथ दिया है, वह कांग्रेस आज इस मसले पर देश भर में प्रेस कांफ्रेंस कर रही है।

भाजपा ने कहा कि आतंकवाद पर प्रेस कांफ्रेंस करने की बजाय , कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। 'कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ' होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि देश में हुई आतंकी घटनाओं में कांग्रेस ने जिस प्रकार से आतंकियों का साथ दिया है, वह सूची बहुत लंबी है।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यासीन मलिक के साथ कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तस्वीर खिंचवाई थी, यूपीए सरकार के दौरान इस आतंकवादी का महिमामंडन किया गया था। बुरहान वानी के संदर्भ में कांग्रेस ने गलत नैरेटिव फैलाया। हाफिज सईद जैसा आतंकी भी दुनिया में सिर्फ एक राजनीतिक दल कांग्रेस की तारीफ करता है।

पात्रा ने सोनिया गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए आगे कहा कि लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर देश के विरोध में धर्म को लेकर एक उन्माद पैदा करने वाले जाकिर नायक के साथ स्वयं सोनिया गांधी खड़ी थी,क्योंकि उनके पति राजीव गांधी जी के नाम पर डोनेशन लिया था। बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों की लाश को देखकर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी फूट-फूट कर रोई थी, ऐसा बयान स्वयं उनके मंत्री सलमान खुर्शीद ने दिया था। राहुल गांधी जेएनयू जाकर अफजल से जुड़े बयानों का समर्थन करते हैं और ये सब भूलकर कांग्रेस आतंकवाद को लेकर देश भर में प्रेस कांफ्रेंस कर रही है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को आतंकवाद के मसले पर देश भर में प्रेस कांफ्रेंस करने की बजाय माफी मांगनी चाहिए, माफीनामा लिखना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से आतंक और आतंकवादियों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस को देश को बताना चाहिए कि उन्होंने चीन के साथ जिस एमओयू पर हस्ताक्षर किया था ,उसमें क्या था ? भाजपा ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के लिए गांधी परिवार आतंकियों के साथ भी गठजोड़ कर सकती है, यही उनका इतिहास रहा है।

युवकों के पैरों में पड़ गए छाले, बीजेपी राज में सरकारी भर्ती पर लटके ताले : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सरकारी नौकरियों में भर्तियों की प्रक्रियाओं का सिलसिला धीरे-धीरे खत्म हुआ है और जिन युवाओं ने नौकरियों के लिए परीक्षाएं दी हैं उन परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किये जा रहे हैं।

सुश्री वाड्रा ने कहा कि वर्ष 2018 में जो बच्चे एसएससी-जीडी परीक्षा की भर्ती में शामिल हुए वे सत्याग्रह कर रहे हैं और उनके पांव में छाले पड़ गए हैं लेकिन सरकार पसीज रही है और भर्तियों पर लगे ताले नहीं खुल रहे हैं। उन्होंने कहा 'एसएससी-जीडी 2018 भर्ती में नियुक्ति के लिए सत्याग्रह कर रहे युवाओं के पैरों में छाले पड़ चुके हैं लेकिन भाजपा राज में सरकारी भर्तियों पर ताले लग चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या इन युवाओं की मेहनत और संघर्ष का कोई मोल नहीं है। इनकी बात सुनिए, नियुक्ति दीजिए।'

इसके साथ ही उन्होंने एक खबर का वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए भाजपा सरकार का छलावा, एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थियों को आज तक नहीं मिला नियुक्ति पत्र। वीडियो में नियुक्ति की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहे कई युवाओं के पांव में चलते-चलते छाले पड़ गए हैं और कई युवतियां बेहोश हो रही हैं।

बीजेपी ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया : संजय निरुपम

पटना, 09 जुलाई (का.सं.)। अखिल भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने शनिवार को यहां भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रवाद के आड़ में देश को अस्थिर रखने की भाजपाई साजिश अब बेनकाब हो चुकी है और आम लोग यह समझ चुके हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर लोगों के दिलों में नफरत और भय का माहौल बनाकर भाजपा देश पर शासन करने की रणनीति पर काम कर रही है।

बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में निरूपम ने भाजपा पर कई आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या भाजपा नेता नूपुर शर्मा के उकसाने के बाद की गई।

उन्होनें कहा कि हालांकि कांग्रेस ने कभी आतंकवाद और आतंकवादियों को लेकर राजनीति नहीं की है और न ही कभी इसे धर्म से जोड़ा है लेकिन हाल की घटनाओं पर सत्तारूढ़ दल की दोतरफा नीतियां अक्षम्य और महापाप की श्रेणी की है।

उन्होंने कहा कि भाजपा देश में छद्म राष्ट्रवाद का प्रचार कर उसके आड़ में देश को राजनीतिक और साम्प्रदायिक तौर पर अस्थिर रखने के एजेंडे पर काम कर रही है। अमरावती में हिन्दू मुस्लिम भावना भड़काने के लिए हिन्दू भाई की हत्यारे हो या अमरनाथ यात्रियों पर हमले में पकड़े गए आतंकियों की जांच हो सभी भाजपा के सक्रिय सदस्य निकलें। देश को सांप्रदायिक हिंसा के आग में झोंकने के प्रयास में भाजपा ने दोनों सम्प्रदाय को दुश्मन बना दिया है।

संवाददाता सम्मेलन की शुरूआत में निरुपम ने अमरनाथ यात्रा में मृत श्रद्धालुओं और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।

वाईएसआर कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष चुने गए जगन मोहन रेड्डी, पार्टी को चुनाव आयोग से लेनी होगी अनुमति

अमरावती, 09 जुलाई (एजेन्सी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी शनिवार को एक बार फिर युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस (वाईएसआरसी) के अध्यक्ष चुने गए। अब वह जीवनभर वाईएसआरसी के अध्यक्ष बने रहेंगे। अमरावती में हो रही वाईएसआरसी की दो दिवसीय वैठक के अंतिम दिन यह प्रक्रिया पूरी हुई। इस दो दिवसीय बैठक में पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया है, ताकि जगन को जीवन भर के लिए अध्यक्ष चुना जा सके।

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद मार्च 2011 में वाईएसआरसी की स्थापना की थी। स्थापना के बाद से वह अपनी मां विजयम्मा और मानद अध्यक्ष के साथ पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले जगन मोहन रेड्डी आखिरी बार 2017 में पार्टी ख़लेनरी में वाईएसआरसी के अध्यक्ष चुने गए थे।

इससे पहले उनकी मां विजयम्मा ने शुक्रवार को पार्टी के मानद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि वह तेलंगाना में अपनी बेटी शर्मिला के साथ काम करने के लिए वाईएसआरसी छोड़ रही हैं। जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला पड़ोसी राज्य तेलंगाना में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं।

पार्टी छोड़ने का एलान करते हुए विजयम्मा ने कहा, 'मैं हमेशा जगन मोहन रेड्डी के संपर्क में रहूंगी। एक मां के रूप में हमेशा जगन के नजदीक रहूंगी।' विजयम्मा ने कहा, 'शर्मिला अपने पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए तेलंगाना में अकेले लड़ाई लड़ रही है। मुझे उसका समर्थन करना है। मैं दुविधा में थी कि क्या मैं दो राजनीतिक दलों (दो राज्यों में) की सदस्य बन सकती हूं। मेरे लिए यह मुश्किल है कि मैं वाईएसआरसी के मानद अध्यक्ष बनी रहूं।'

गत कुछ समय से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन शर्मिला के बीच संपत्ति से जुड़े मुद्दों को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल के दिनों में दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई थी। इसके बाद विजयम्मा अपने बेटे से दूर रहती थीं।

नियमों के मुताबिक, वाईएसआरसी को अब जगन को आजीवन पार्टी प्रमुख बनाए रखने के लिए भारत के चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। वाईएसआरसी ने इस बाबत अन्य राज्यों में कुछ क्षेत्रीय दलों द्वारा हर दो साल में चुनाव कराने की आवश्यकता के बिना जीवन भर के लिए एक अध्यक्ष रखने के लिए ईसीआई की मंजूरी हासिल करने का उदाहरण भी दिया है।

यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 2 महिलाओं की मौत, 50 लोग बचे

डांग (गुजरात), 09 जुलाई (एजेन्सी)। गुजरात के डांग जिले में सापुतारा के पास यात्रियों से भरी एक बस के खाई में गिरने से दो महिला यात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए जबकि 50 यात्रियों को बचा लिया गया है। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है।

पुलिस ने बताया कि बस सापुतारा से वाघई जा रही थी तभी मालेगांव के पास टायर फटने से यह हादसा हो गया। मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि डांग जिले के सापुतारा के पास 50 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक बस खाई में गिर गई। दो महिला यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 50 यात्रियों को बचा लिया गया है। यह दुर्घटना टायर विस्फोट के कारण हुई।

सेना के ब्लैक कैट डिविजन ने मनाया 'जॉय ऑफ गिविंग'

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 09 जुलाई । सेना के ब्लैक कैट डिवीजन ने सिक्किम के किड्स हॉस्टल ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन में 'जॉय ऑफ गिविंग' मनाया।

इसमें एफडब्ल्यूओ अध्यक्ष 17 माउंटेन डिवीजन और ब्लैक कैट लेडीज ने छात्रावास के 44 बच्चों को कई आवश्यक सामग्रियां, स्टेशनरी और साइकिल भेंट की। सेना की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई।

इसमें कहा गया कि देने का कार्य आनंदमय होता है जब वह बिना शर्त और दिल से होता है, तो देने के पीछे की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। उपहार प्राप्त करना एक अच्छा एहसास है। जब हम देते हैं और बांटते हैं तो हमारा जीवन परिपूर्ण होता है, और वह महान आंतरिक आनंद दूसरों को उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है।

प्रभावितों को दी .....

को टेपुंग गांव में हुई इस पहल के तहत 250 से अधिक ग्रामीणों में उनके विभिन्न कार्यों के प्रमाणपत्र वितरित किये गये।

दिन भर चले इस कार्यक्रम के दौरान एसडीएम भूटिया के साथ ही राजस्व अधिकारी अमृत राज राई, प्रमुख सर्वेक्षक सागर लिम्बू, राजस्व सर्वेक्षक सोनम छिरिंग भूटिया के अलावा कार्यालय कर्मी दिलवा लेप्चा, अनिता लिम्बू एवं एसडीएम कार्यालय के अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान रिम्बिक-टिम्ब्रोंग ग्राम पंचायत अध्यक्ष मंगल राई ने इस पहल के लिये एसडीएम भूटिया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एसडीएम श्री भूटिया की पहल पर आयोजित होने वाले 'द्वार पर प्रशासन' कार्यक्रम से ग्रामीणों को बहुत फायदा हुआ है। वहीं उन्होंने भूस्खलन पीड़ितों की सहायता हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें पुनर्वासन हेतु जमीन के पर्चे दिये जाने की भी उन्होंने सराहना की।

भारत का युवा नौकरी तलाशने की जगह नौकरी देने वाला : राष्ट्रपति कोविंद

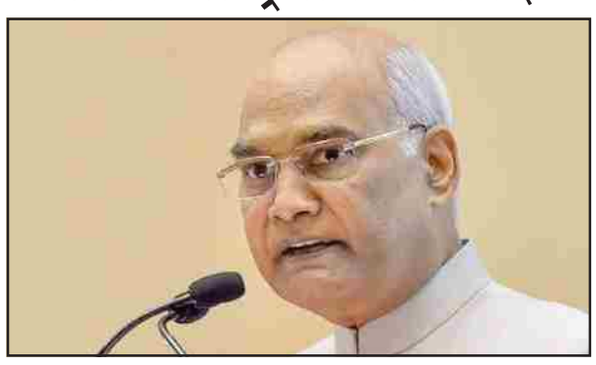

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को माई होम इंडिया की तरफ से आयोजित किए गए युवा सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। सम्मेलन में बोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य युवाओं पर टिका होता है। उनकी क्षमता और प्रतिभा ही देश को गौरवान्वित करने में अहम भूमिका निभाती है। दुनिया में भारत ही सबसे ज्यादा युवा वाला देश है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज का युवा नौकरी तलाशने की जगह नौकरी देने वाला बन रहा है। लिहाजा यह कहना उचित होगा कि आज का युवा कल का इतिहास निर्माता है। देश का भविष्य युवाओं के उद्यम और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को हर अवसर का लाभ उठाते हुए देश के विकास और प्रगति में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान देना चाहिए।

इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कौशल हासिल कर युवा उसी के अनुसार अपना करियर निर्धारित करें। यह युग विशेषज्ञताओं का है। शीर्ष पर पहुंचने के लिए युवाओं में तकनीकी और विशेषज्ञता होनी बेहद जरुरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में 29 जून 2022 तक 103 यूनिकॉर्न स्थापित किए गए हैं, इनका कुल मूल्यांकन लगभग 336 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दुनिया के हर दस में से एक यूनिकॉर्न भारत में है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 47 कंपनियों ने मई 2022 तक डेकोकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। जिनमें से चार भारतीय स्टार्ट-अप हैं। तीन स्टार्ट अप युवाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने वैश्विक स्तर पर परेशानियां खड़ी की थी, लेकिन देश के युवा उद्यमियों ने हौसला नहीं खोया और प्रतिभा का एक उदाहरण पेश किया। भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व में हमें अलग करती है। यह बहुत ही पुरानी है। भारत ने हमेशा अनेकता में एकता के सिद्धांत को अपनाया है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि माई होम इंडिया राष्ट्रीयस्तर पर एकता और अखंडता की भावना का प्रचार कर रही है। यह बेहद खुशी की बात है। राष्ट्रवाद को फैलाना युवा सम्मेलन एक सराहनीय प्रयास है।

दरमदिन फुटबॉल क्लब फाइनल में

अनुगामिनी नि.सं.

सोरेंग, 09 जुलाई । सिक्किम के कृषि व बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष सीके राणा ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी खेलकूद एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से ग्रामीण प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभाएं दिखाने का एक अच्छा मंच प्राप्त होगा। बोर्ड अध्यक्ष आज जिले के यांगथोंग सृजन क्लब के तत्वावधान में आयोजित खुली फुटबॉल प्रतियोगिता के 13वें दिन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे।

इस दौरान अपने वक्तव्य में सीके राणा ने कहा कि इस प्रकार के खेलकूद आयोजनों से युवाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा एवं अन्य नशीले एवं मादक पदार्थों से छुटकारे में भी मदद मिलेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता आयोजक समिति यांगथोंग सृजन क्लब की सराहना भी की। इस अवसर पर दरामदिन समष्टि के युवा संयोजक रमेश गुरुंग, जिला पंचायत जीवन गुरुंग, कार्थोक प्रखंड पंचायत उपाध्यक्ष पासांग लेप्चा के अलावा आमंत्रित अतिथिगण भी मौजूद रहे। आज प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मैच में दरमदिन फुटबॉल क्लब ने चाखुंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन को ट्राई ब्रेकर में 2 के मुकाबले 3 गोल कर पराजित कर फाइनल में अपनी जगह बना ली। वहीं सुम्बुक और कार्थोक टीमों के बीच खेले गये दूसरे सेमीफाइनल मैच में सुम्बुक की टीम विजयी रही। ऐसे में फाइनल में दरमदिन फुटबॉल क्लब और सुम्बुक की टीमें आमने-सामने रहेंगी।

प्रतियोगिता आयोजन समिति द्वारा विजेता टीम को 40 हजार रुपये और उप-विजेता टीम को 30 हजार रुपये की नगद धनराशि के साथ आकर्षक ट्रॉफियां प्रदान की जायेंगी। इस प्रतियोगिता में कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया था।

भगौड़े विजय माल्या की सजा पर 11 जुलाई को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सजा सुनाएगा। जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली, रवींद्र एस भट और पीएस नरसिम्हा की तीन जजों की बेंच सोमवार को फैसला सुनाएगी। पीठ ने मामले में 10 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साल 2017 में विजय माल्या को दोषी ठहराया था।

मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माल्या यूनाइटेड किंगडम में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है और उससे संबंधित कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। सजा पर फैसला सुरक्षित रखने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 'हमें बताया गया है कि (माल्या के खिलाफ) ब्रिटेन में कुछ मुकदमे चल रहे हैं। हमें नहीं पता, कितने मामले लंबित हैं। मुद्दा यह है कि जहां तक हमारे न्यायिक अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है तो हम कब तक इस तरह चल पाएंगे।'

वहीं, सुनवाई के दौरान माल्या के वकील कहा कि ब्रिटेन में रह रहे उनके मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिल सका है इसलिए वह पंगु हैं और अवमानना के मामले में दी जाने वाली सजा की अवधि को लेकर उनका (माल्या का) पक्ष रख पाने में असहाय हैं। इससे पहले कोर्ट ने माल्या को दिए गए लंबे वक्त का हवाला देते हुए 10 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय कर दी थी और भगोड़े कारोबारी को व्यक्तिगत तौर पर या अपने वकील के जरिए पेश होने का अंतिम मौका दिया था।

माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था और उनकी प्रस्तावित सजा के निर्धारण के लिए मामले को सूचीबद्ध किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका 2020 में खारिज कर दी थी। न्यायालय ने अदालती आदेशों को धता बताकर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने को लेकर उन्हें अवमानना का दोषी माना था।

पीएम मोदी ने जनता का दम निकाल दिया है : राहुल

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज में पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के साथ ही गब्बर सिंह टैक्स' की लूट एवं बेरोजगारी की सुनामी आ गई है। राहुल ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने कहा-133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं, दम है तो हमें रोको।

भाजपा राज में एलपीजी सिलिंडर की कीमतें 157 प्रतिशत बढ़ीं, रिकॉर्ड-तोड़ महंगा पेट्रोल, गब्बर सिंह टैक्स' की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, असल में जनता प्रधानमंत्री से कह रही है-आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, अब रुक जाओ।

वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने अमरनाथ यात्रा त्रासदी को लेकर संवेदना प्रकट की थी जिसमें उन्होंने एक ट्विट कर लिखा था कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कई श्रद्धालुओं के लापता होने और मृत्यु की ख़बर बेहद दु:खद है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।

दिल्ली हाईकोर्ट की जामिया को दो टूक

'अपनी संपत्ति बेचें और प्रोफेसर का वेतन दें'

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र के लिए धन जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जामिया यूजीसी से धन प्राप्त करने के लिए अदालत की ढाल नहीं ले सकता है।

अदालत ने सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र की निदेशक के रूप में कार्यरत एक प्रोफेसर द्वारा अपने वेतन के भुगतान की मांग करने वाली एक लंबित याचिका के संबंध में जामिया की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक आदेश पारित किया। जामिया ने यह कहते हुए आवेदन दाखिल किया था कि यूजीसी द्वारा नियमित बजट या 'भारतीय विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास' की योजना के तहत सहायता नहीं देने के कारण प्रोफेसर के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है।

विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि वह आयोग को अनुदान जारी करने और योजना के तहत छह करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दे। हालांकि, हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जब विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार सहित अन्य सभी अधिकारियों को वेतन मिल रहा है तो संबंधित शिक्षक को क्यों नहीं?

अदालत ने कहा कि आप अपनी संपत्ति बेचें और पैसे का भुगतान करें। यूजीसी से पैसे लेने के लिए आप अदालत की ढाल नहीं ले सकते। अपने कुलपति और रजिस्ट्रार से कहें कि वे अपना वेतन रोक दें और संबंधित शिक्षक को भुगतान करें।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्म प्रसाद की बेंच ने कहा कि अन्य सभी अधिकारियों को वेतन देने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन संबंधित शिक्षक के लिए आप चाहते हैं कि हम यूजीसी को निर्देश दें। कुलपति और रजिस्ट्रार को वेतन

मिल रहा है, लेकिन गरीब शिक्षक को नहीं।

जामिया के स्थायी वकील प्रीतिश सभरवाल ने दलील दी कि यह केंद्र यूजीसी का है और विश्वविद्यालय इसे यूजीसी की योजना के तहत चला रहा है। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय को केंद्र के विलय के लिए पत्र भेजा था, न कि शिक्षण पदों के लिए। शिक्षकों के वेतन के लिए धन यूजीसी से आना है, जिसने अनुदान जारी करना बंद कर दिया है।

बेंच ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह प्रोफेसर को सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा। बेंच ने कहा कि अदालत ने जामिया का आश्वासन स्वीकार कर लिया था और कहा था कि प्रोफेसर को मासिक आधार पर तय समय पर वेतन का भुगतान जारी रहेगा।

छह जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा पूछे गए एक विशिष्ट सवाल पर कि क्या कुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, विश्वविद्यालय के वकील ने हां में जवाब दिया था।

हाईकोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह आवेदन कुछ और नहीं, बल्कि पिछले आदेश को दरकिनार करने का प्रयास है, जो एक सहमति आदेश था। हमें आवेदन पर विचार करने की कोई वजह नजर नहीं आती है। लिहाजा इसे खारिज किया जाता है।

देश में उच्च शिक्षा आयोग बनाने पर चल रहा काम : धर्मेंद्र प्रधान

वाराणसी, 09 जुलाई (एजेन्सी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब देश में उच्च शिक्षा आयोग बनाने पर काम चल रहा है। शिक्षाविदों को न सिर्फ इस दिशा में पहल के साथ अपने जरूरी सुझाव भी देने चाहिए। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के विदाई सत्र में उन्होंने देशभर के शिक्षाविदों से कहा कि हमें भारत के एकलव्यों को ढूंढकर निकालना होगा।

तीन दिन के 11 सत्रों के बाद शनिवार दोपहर शिक्षा समागम का विदाई सत्र हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि 11 सत्रों में शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की राह में आने वाली चुनौतियों और अब तक मिली सफलताओं पर चर्चा हुई, कई बेहतरीन सुझाव सामने आए। बताया कि समागम में देश के 380 संस्थानों के प्रमुखों को न्योता दिया गया था जिनमें 350 शामिल हुए। सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समान रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्री ने सिकंदर से जुड़े एक प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया जीतने के बाद भारत का रुख करने वाले सिकंदर को लौटना पड़ा। जाते हुए उसने कहा कि इस देश को कोई बाहरी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसे हराने के लिए इसके एजुकेशन सिस्टम को हराना होगा। उन्होंने कहा कि 1835 से देश में लागू मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम को बदलकर अब शिक्षा व्यवस्था को जड़ों की तरफ लौटाने का वक्त है।

शिक्षाविदों का आह्वान करते हुए उन्होंने अनुसंधान, अविष्कार और आंत्रप्रेन्योर तैयार करने पर जोर दिया।

कहा कि इंडस्ट्री के हिसाब से यूनिवर्सिटी को बदलना होगा वरना आगे चुनौतियां गंभीर होती जाएंगी। कहा कि हम ज्ञान दानी लोग हैं। अब तनख्वाह और पेंशन से आगे बढ़कर मल्टी डायमेंशिनल, मल्टी डिसीप्लिनरी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रेडिट अरेंजमेंट और इंस्टीट्यूशन से फुलप्रूफ छात्र तैयार करने का वक्त है। क्षेत्रीय भाषाओं पर उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदी, बांग्ला और तेलुगू को मिला दें तो हम दुनिया की सबसे बड़ी भाषा वाले देश बन सकते हैं।

भारत में धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं : उपराष्ट्रपति

'कुछ लोगों को प्रगति पच नहीं रही'

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को जोर देकर कहा कि भारत दुनिया का सबसे सहिष्णु देश है। उन्होंने कहा कि देश में धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित है और यह किसी सरकार की वजह से नहीं है बल्कि इसलिए है कि यहां रहने वाले हर व्यक्ति की खून और धमनियों में यह भावना बहती है। नायडू ने इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में देने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हमारा देश महान है। सौभाग्य से भारत फिर उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और दुनिया अब इसे मान रही है और एक बार फिर भारत का सम्मान कर रही है, हमें कोई नजर अंदाज नहीं कर सकता। हालांकि, कुछ लोग यहां-वहां छोटी चीजें लिख सकते हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग भारत की प्रगति को पचा नहीं सकते, वे अपच के शिकार हैं। हम उनकी मदद नहीं कर सकते।''

माउंट कार्मेल इंस्टीट्यूशन की ख्रलेटिनम जुबली' पर यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि पश्चिमी मीडिया भारत के बारे में बहुत ही नकारात्मक खबरें दे रही है, वे इस देश और यहां के लोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की जा रही बड़ी उपलब्धियों को भूल जाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि देश के समक्ष सामाजिक अंतर, गरीबी, लैंगिक असमानता जैसी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत, औपनिवेशिक शासन में विश्वास नहीं करता और या वह दूसरे देश पर अपनी मर्जी नहीं थोपता, भारत का किसी देश पर हमला नहीं करने का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा, ...भारत दुनिया का सबसे सहिष्णु देश है, जिसपर कोई भी भरोसा कर सकता है। लोग धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा करते हैं, धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित है, इसलिए नहीं की यह सरकार या वह सरकार, यह पार्टी या वह पार्टी ऐसा चाहती है। बल्कि यह इसलिए है क्योंकि यहां के हर व्यक्ति के खून और धमनियों में यह है और यह सभी को समझना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे कोई और देश दिखा दीजिए, जहां सभी वर्गों को समान अवसर दिया जाता है। वे क्या हैं, कुछ लोग हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए उन देशों के अंदर क्या हो रहा है, उन कथित अमीर देशों में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। प्रगति के लिए शांति को पहली शर्त बताते हुए नायडू ने कहा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गेट अल्वा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। अल्वा इस संस्थान की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं।

उपराष्ट्रपति ने लोगों को अपनी भाषा और धर्म पर गर्व करने की सलाह दी, साथ ही कहा कि दूसरे को अपमानित नहीं करें। उन्होंने कहा, हम यहां -वहां कुछ लोगों

को देख रहे हैं जिनकी कमजोरी दूसरों को अपमानित करने और उससे आनंदित होने की है, जो ठीक नहीं है। प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है। हमें धर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, धर्म व्यक्तिगत पूजा करने का तरीका है। हमें अधिक हमारी संस्कृति और विरासत पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जो हमारे जीवन जीने का तरीका है।''

नायडू ने कहा कि वह मातृभाषा में बात कर खुशी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में होनी चाहिए क्योंकि इससे समझने, सीखने और संवाद करने में आसानी होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा, मातृभाषा,मां की तरह है। मुझे खुशी है कि हम फिर से जड़ों की हो जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, इसके बाद हम भ्रातृ भाषा और अन्य भाषा की ओर जा सकते हैं, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है...मातृ भाषा आपकी आंखों की तरह होती है, बाकी भाषाएं चश्मे की तरह होती हैं, अगर आपकी आंखे ठीक हैं तो चश्मे भी सही काम करेंगे।'' उन्होंने खुशी जताई कि नई शिक्षा नीति में मातृ भाषा को महत्व दिया जा रहा है। नायडू ने साथ ही कहा कि वह अन्य भाषाओं के खिलाफ नहीं हैं। उपराष्ट्रपति ने 4सी कैरेक्टर (चरित्र), कैलिबर (क्षमता), कपैसिटी (योग्यता) और कंडक्ट (आचरण) के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से मौजूदा परिपाटी यह है कि कुछ लोग इन 4सी को दूसरे 4सी कास्ट (जाति), कम्युनिटी (समुदाय), कैश (नकद) और क्रिमनैलिटी (अपराध) से बदलना चाहता हैं, जो केवल अस्थायी बढ़त दे सकती है।

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR OSTRICH EVENING
SATURDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:184 DrawDate on:09/07/22
1st Prize ₹1 Crore/- 44H 69884
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 69884 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
01233 07861 26559 27907 37032 37276 45644 65076 75279 87778
3rd Prize ₹450/-
0333 0446 3289 5683 6640 7227 8133 9467 9527 9922
4th Prize ₹250/-
0274 3394 4005 4212 5209 5532 6374 7622 8439 9393
5th Prize ₹120/-
0076 0106 0248 0342 0373 0378 0411 0850 0984 1039
1162 1380 1442 1535 1611 1786 2061 2137 2835 3142
3259 3453 3474 3510 3565 3663 3888 4269 4347 4516
4539 4606 4827 5024 5043 5045 5072 5111 5225 5235
5254 5332 5347 5418 5503 5528 5564 5580 5762 5822
5951 6089 6113 6138 6268 6274 6323 6376 6378 6692
6877 7026 7200 7269 7320 7360 7370 7484 7521 7523
7625 7638 7746 7774 7892 7979 8066 8218 8275 8309
8372 8376 8380 8503 8522 8771 9104 9145 9165 9192
9196 9201 9331 9367 9444 9504 9640 9669 9925 9948
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR MARS SATURDAY
WEEKLY LOTTERY
Draw No:84 DrawDate on:09/07/22
1st Prize ₹1 Crore/- 87H 87489
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 87489 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
03706 05037 11870 13229 17133 29431 31852 33459 69108 81153
3rd Prize ₹450/-
1976 3234 3290 4466 4688 6132 7562 7651 8455 9030
4th Prize ₹250/-
1874 2472 3536 4785 5175 5733 6081 7909 8876 9104
5th Prize ₹120/-
0104 0186 0202 0214 0232 0247 0253 0368 0406 0638
0749 1152 1298 1373 1488 1532 1828 1841 1869 2015
2184 2194 2353 2508 2582 2591 2639 2773 2783 2886
2905 3174 3190 3452 3522 3526 3978 4053 4140 4177
4376 4391 4523 4891 4904 4965 4973 5180 5208 5363
5364 5445 5552 5684 5762 5923 6049 6094 6120 6313
6315 6506 6608 6643 6667 6773 6861 6891 6905 6912
6913 6923 6957 7110 7503 7513 7582 7662 7859 7992
8041 8066 8234 8330 8516 8822 8905 8927 9056 9097
9134 9142 9210 9240 9241 9264 9283 9650 9663 9798
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR KOSAI MORNING
SATURDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:84 DrawDate on:09/07/22
1st Prize ₹1 Crore/- 92D 26553
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 26553 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
07397 09908 14020 25610 32376 37774 39406 53040 94999 98973
3rd Prize ₹450/-
2591 2682 3675 5120 5293 7660 7717 8919 8950 9219
4th Prize ₹250/-
1180 1685 2236 3224 5231 7251 7650 8401 9398 9728
5th Prize ₹120/-
0161 0259 0755 0756 0882 0927 1028 1192 1235 1548
1549 1590 1701 1774 1845 1928 2090 2200 2521 2542
2563 2646 2769 2821 2837 2966 2977 3198 3225 3274
3289 3478 3863 3955 3991 4015 4023 4093 4117 4343
4355 4622 4648 4741 4761 4769 4879 4926 5091 5106
5164 5414 5502 5587 5603 5894 6013 6176 6328 6430
6452 6472 6651 6715 6825 7000 7053 7085 7106 7112
7184 7239 7305 7419 7779 7909 8096 8452 8594 8628
8634 8636 8676 8712 8733 8843 8917 8994 9031 9286
9316 9385 9452 9499 9582 9635 9658 9743 9787 9913
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

भारतीय अदालतों में करीब पांच करोड़ मामले लंबित : रिजिजू

'वकीलों की मोटी फीस पर जगाई चिंता'

मुम्बई, 09 जुलाई (एजेन्सी)। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को देशभर की अदालतों में लंबित मामलों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश भर की अदालतों में फिलहाल पांच करोड़ मामले लंबित हैं। यदि इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यह संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी।

केंद्रीय मंत्री ने ये बातें महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एमएनएलयू), औरंगाबाद में आयोजित पहले दीक्षांत समारोह में कहीं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि आम जनता के लिए कानून पेशेवर सामर्थ्य से बाहर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं। उन्होंने कहा, दो दिन पहले मैं लंदन में था, वहां मैं न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों से मिला। उनके मन में भारतीय न्याय प्रणाली के लिए बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का ब्रिटेन में उल्लेख किया जाता है। कानून मंत्री ने कहा कि यह स्थिति न्याय प्रदान में अक्षमता या सरकार से समर्थन में कमी के कारण पैदा नहीं हुई है। यदि कुछ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती ही जाएगी।

उन्होंने कहा कि भारत में जजों पर दबाव का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन में जहां जज दिनभर में तीन से चार मामले पर ही फैसला सुनाते हैं। वहीं, भारत में जजों को 40-50 मामलों पर फैसला सुनाना पड़ता है। उन्होंने इस दौरान वकीलों की मोटी फीस पर भी चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में मध्यस्थता बिल को कुछ संशोधन के साथ लाया जाएगा।

सीएम गहलोत ने अमित शाह के सामने उठाया ईआरसीपी का मुद्दा, पीएम मोदी का नाम लेकर इशारों में कसा तंज

जयपुर, 09 जुलाई (एजेन्सी)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30 वीं बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का मुद्दा उठाया। सीएम ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप राज्यपाल समेत कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया. बैठक में एजेंडे में शामिल कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए आश्वासन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान के लिए एक अतिरिक्त पूर्णकालिक सदस्य का पद सृजित करने की मांग भी की। गहलोत ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों को रखने के साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नवाचारों से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की परिस्थितियों एवं राजस्थान के व्यापक हित में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य का एक अतिरिक्त पद राजस्थान के लिए सृजित होना चाहिए। श्री गहलोत ने सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को प्रभावी तरीके से लागू करने की बात रखी। राज्य में जनाधार पोर्टल के जरिए 1 जुलाई 2022 तक लगभग 116 करोड़ ट्रांजेक्शन से लगभग 56 हजार करोड़ रूपये (संचयी रूप से) के प्रत्यक्ष लाभ तथा वर्ष 2022 के 5 माह में लगभग 6000 करोड़ रूपये के प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में भौगोलिक चुनौतियों से जल जीवन मिशन (जेजेएम) में हर घर तक नल से जल पहुंचाने में अधिक समय लग रहा है। मिशन की समय-सीमा 31 मार्च 2026 की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्त पोषण पैटर्न को 90:10 किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पात्र प्रदेशवासियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाने के लिए बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर सीलिंग पुन: निर्धारित कर राज्य के लिए लाभार्थियों की वितरण सीमा 4.46 करोड़ से बढ़ाकर 5.24 करोड़ करनी चाहिए।

सीएम गहलोत ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि जून 2022 से बढ़ाकर जून 2027 तक करने के लिए कहा। साथ ही वर्ष 2017-18 से मई 2022 तक राजस्थान को देय जीएसटी मुआवजे के लगभग 5000 करोड़ रूपये की बकाया राशि एकमुश्त जारी करने की मांग रखी। गहलोत ने राज्य में जल संबंधित मुद्दों के समाधान की आवश्यकता बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। ईआरसीपी 37,247 करोड़ रूपये की महत्वाकांक्षी परियोजना है, इससे राज्य के 13 जिले लाभांवित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी विभिन्न अवसरों पर इस परियोजना के लिए सकारात्मक रूख रखने का वादा किया था।

संपादकीय पृष्ठ

याद रखेगी दुनिया

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शुक्रवार की दोपहर हत्या हो गई, जिसके साथ भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दोस्त गंवा दिया। पश्चिम जापान के नोरा शहर में शुक्रवार को वह लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्हें एक व्यक्ति ने पीछे से गोली मार दी थी। वह रविवार को होने वाले ऊपरी सदन के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, जब यह घटना हुई। आबे जापान के इतिहास में प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले नेता थे। वह 2012 से 2020 तक प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले वह 2007 में भी एक साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में जापान में राजनीतिक स्थिरता का श्रेय आबे को जाता है। उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने जापान की इकॉनमी को सुधारने के लिए ब्याज दरों में अप्रत्याशित कटौती और रेग्युलेटरी रिफॉर्म्स किए। इन नीतियों को आबेनॉमिक्स कहा गया। उन्होंने जापान को डिफ्लेशन से बचाया।

आबे चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधारने की पहल की। जब वह 2012 में प्रधानमंत्री बने, तब चीन के साथ जापान के रिश्ते बहुत खराब थे। लेकिन चीन के साथ जब दक्षिण चीन सागर के सेनकाकू द्वीपों को लेकर तनाव बढ़ा तो उन्होंने चीन के प्रति आक्रामक रुख अपनाया। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ जापान क्वॉड में शामिल हुआ। यूं तो इसका आइडिया 2007 में पहली बार जापान की ओर से आया था, लेकिन 2017 में जब इसे एक शक्ल दी गई, तब आबे ही जापान के प्रधानमंत्री थे। आज यही क्वॉड हिंद-प्रशांत और एशिया में चीन के खिलाफ एक अहम मंच है। चीन और अमेरिका के बीच जो नया शीत युद्ध शुरू हुआ है, भविष्य में उसमें क्वॉड अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत के लिए आबे का योगदान इतना ही नहीं है। जब वह 2007 में प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार भारत आए थे, तब उन्होंने यहां संसद को संबोधित किया था।

जापान यूं तो भारत का पारंपरिक सहयोगी और मददगार रहा है, लेकिन आबे ने इस रिश्ते को और मजबूत बनाया। खासतौर पर मोदी के साथ उनकी कमाल की केमिस्ट्री थी। दोनों पहली बार 2007 में आबे की भारत यात्रा के दौरान मिले थे। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने 2012 में जापान, 2014 में दिल्ली में आबे से मुलाकात की। इस दोस्ती की वजह उनकी समान सोच है। आबे ऐसा जापान चाहते थे, जो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। मोदी भी मजबूत भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए आबे के निधन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने देश में 9 जुलाई को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का एलान किया। मोदी ने भारत-जापान के रिश्तों को नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए आबे के योगदान को याद किया। आबे चले गए हैं, लेकिन भारत के साथ रिश्तों की जो बुनियाद उन्होंने तैयार की, वह आगे और मजबूत होगी।

विश्व कूटनीति का केंद्र भारत

प्रो. सतीश कुमार

पिछले दिनों यूक्रेन युद्ध को लेकर अंतराष्ट्रीय जगत में खूब गहमागहमी बनी रही। कई सम्मलेन भी हुए।

कई देशों के विदेश मंत्री का आना जाना भी हुआ। ब्रिक्स और जी 7 का वार्षिक सम्मेलन भी सम्पन हुआ। हर देश की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। भारत क्या निर्णय लेता है? क्या भारत की निर्णय पद्धति को बाहरी दबाव में बदला जा सकता है?

यह विचार-विमर्श देश के भीतर और बाहर दोनों जगह था। दरअसल, ऐसा प्रयास भारत की विदेश नीति में पहली बार अंकित हुआ है, इसके पहले भारतीय निर्णय बदले जाते थे और भारत मूकदर्शक बनकर दुनिया की कूटनीति का एक लाचार मोहरा बन जाता था। इसलिए यह समझना ज्यादा जरूरी है कि बाहर और भीतर क्या कुछ बदला, जिसने भारत की साख को दुनिया के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया? बदलाव भीतर से ज्यादा हुआ। उसकी चर्चा ज्यादा जरूरी है। पहला; 8 वर्षो में बिग डाटा के साथ भारत की तस्वीर बदलने लगी। आधार कार्ड और उसके तर्ज पर हर व्यक्ति के जुड़ाव ने देश की सामाजिक और आर्थिक सांचे को बुनियादी तौर पर बदलना शुरू कर दिया। सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ आधार का पंजीकरण न केवल नियमता को बहाल किया बल्कि भ्रष्टाचार को भी समेटने का सफल प्रयास किया। जनधन योजना, उज्जवला और अनेकों प्रयास में बिग डाटा गेम चेंजर बना। दूसरा; भारत का आर्थिक प्रयास 2014 के पहले तक मैक्रो आर्थिक इकाई पर बनती थी, वही मुख्य फोकस होता था। अर्थात विकेंद्रीकरण की बात केवल किताबों की कहानी बन कर रह जाती थी, वह तरीका बदल गया। माइक्रो सोच इस सरकार की मुख्यधारा बन गई। जगह और समूह को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जाने लगी। उसका अनुपालन भी उसी रूप में होने लगा। तीसरा; भारत की आर्थिक योजनाओं की मलाई अक्सर इलीट वर्ग समेट लेता था। इलीट वर्ग का निर्माण भी बहुत हद तक भाषा के तर्ज पर बनता था। अंगेरजी पढ़ने और लिखने वाले हर तरह से फायदे में रहते थे। गांव और कस्बे के लोग शेष बचे हुए अंश से संतुष्ट होते थे, लेकिन पिछले 8 साल में यह पद्धति बदल गई। हाशिये पर रहने वाले आगे आने लगे मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ, उनकी आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत हुई। चौथा; सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग महज महिला, अनुसूचित जाति और भूमिहीन किसान तबका बुनियादी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से मजबूत हुए हैं। चाहे वह डिजिटल आर्थिक परिवर्तन की बात हो या तीन तलाक की चर्चा हो। अंदरूनी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन ने भारत को मिडिल पावर की श्रृंखला के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। भारत के विभिन्नता में एकता के सिद्धांत को खूब प्रसारित किया गया। अर्थात भारत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से अलग अलग है। हमारे नीति-निर्माताओं ने एकता की बात को गौण कर दिया और विभिन्नता की तस्वीर को मजबूत आवरण से मढ़ दिया।

भारत को कई टुकड़ों में बांटने की बात ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल करते थे। अमेरिका और चीन के `ेत पत्र भी भारत के विखंडन की कहानी रची और प्रचारित की जाती थी। कभी भी भारत की सरकार ने इन विषमताओं को चुनौती देने का गंभीर अकादमिक प्रयास नहीं किया। नतीजा भारत का स्वरूप टूटे हुए आईना में टुकड़े-टुकड़े में दिखाई देने लगा। इस सरकार ने भारत को एक सांचे में ढालने की कोशिश की। उसका फायदा भी दिखाई देने लगा। इसलिए बाहरी व्यवस्था भी भारतीय दृष्टिकोण से बदलने लगी। इसके कई उदाहरण हैं। पहला, ब्रिक्स का विस्तार चीन अपने नक्शेकदम पर करना चाहता है। जी-20 संगठन से कुछ देशों को ब्रिक्स में शामिल करना चाहता है, जिसमें एक इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया को लेकर ज्यादा हुज्जत नहीं होगी। क्योंकि भारत के संबंध अच्छे हैं।

अफ्रीका के दो महत्त्वपूर्ण देश नाइजीरिया और सेनेगल को शामिल करने की कोशिश चीन करेगा। इनके शामिल होते ही दक्षिण अफ्रीका की अहमियत ढीली पड़ जाएगी। साउथ अफ्रीका की अनुशंसा के बिना इनको खेमे में लेना ब्रिक्स के लिए विघटन का कारण बन सकता है। उसी तरह अज्रेंटीना के संबंध ब्राजील से अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा चीन की सूची में कई देशों के नाम हैं।

चीन की पूरी कोशिश एक नये खेमे की व्यूह रचना की है, जो अमेरिकी सांचे में खलल पैदा कर सके। एक मिडिल पावर का नई हुजूम खड़ा करने में सफल हो जो जी-7 और अन्य अमेरिकी निर्देशित संघटन को चुनौती दे सके। दूसरा, ब्रिक्स का आर्थिक आधार अभी भी बहुत कमजोर है, जबकि 5 देशों की कुल आबादी तकरीबन दुनिया की आधी आबादी के नजदीक है, 25 फीसद कुल वैश्विक जीडीपी का हिस्सा है। फिर भी 15 वर्षो में इसकी धार और कुंद हुई है। आर्थिक विकास की राह में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से सुस्त पड़ गए। आपसी व्यापार मुश्किल से 20 फीसद से ज्यादा नहीं है। क्या ऐसे हालत में इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन या जी-7 की बराबरी कर सके। तीसरा, यूक्रेन युद्ध ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। विश्व पुन: दो खंडों में विभाजित दिख रहा है। नये शीत युद्ध का आगाज हो गया है। दरअसल, चीन इस युद्ध को लेकर अपनी चौकड़ी बनाने की कवायद में लगा हुआ है। चूंकि सैनिक रूप से मजबूत रूस आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर है, युद्ध ने उसकी स्थिति को और जर्जर बना दिया है, इसलिए चीन रूस को लेकर एक ऐसी टीम बनाना चाहता है जो उसे दुनिया का मठाधीश बनाने का स्वख्वन पूरा कर सके। इसके लिए वह अमेरिका से ताइवान पर युद्ध के लिए भी आमादा है।

चौथा, चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया के सामने है। श्रीलंका, पाकिस्तान, मलयेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देश चीन का दंश झेल रहे हैं। चीन ने पिछले कुछ वर्षो में जिस तरीके से विश्व की व्यवस्था को अपने तरीके से संचालित करने की साजिश रची है उससे दुनिया सहमी हुई है। भारत की नई शक्ल उसकी अंदरूनी क्षमता के कारण बनकर तैयार हुई है। इसलिए यह टिकाऊ और मजबूत है। चीन से बचने और एक बेहतर दुनिया का निर्माण भारत के साथ ही बन सकता है।

कट्टरता के दौर में कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं

तस्लीमा नसरीन

पिछले दिनों बांग्लादेश के नड़ाइल में मिर्जापुर यूनाइटेड कॉलेज के प्रोफेसर स्वख्वन कुमार बसु और एक छात्र को उपस्थित भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में जूते की माला पहनाई। उन दोनों की गलती क्या थी? छात्र की गलती यह थी कि उसने भारत में चल रहे विवाद के बीच भाजपा से निलंबित नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। और प्रोफेसर की गलती क्या थी? उनकी गलती यह थी कि जब क्रुद्ध भीड़ उस छात्र को मारने के लिए उसका पीछा कर रही थी, तब प्रोफेसर ने अपने चेंबर में उस छात्र को शरण दी थी।

भीड़ ने कॉलेज कैंपस में ही प्रोफेसर के स्कूटर में आग लगा दी। प्रोफेसर ने पुलिस बुला ली। लेकिन पुलिस के जवानों ने प्रोफेसर और छात्र को सुरक्षा देने के बजाय उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया, ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके और जूते की माला पहनाई जा सके।

नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर सिर्फ नड़ाइल नहीं, पूरे बांग्लादेश में कट्टरवादियों ने तांडव मचाया था। उन कट्टरवादियों को संभवत: यह मालूम भी नहीं था कि उनके क्षुब्ध होने की वजह क्या है, आखिर विवादास्पद टिख्वपणी में कहा क्या गया था।

वर्षों पहले जब मैंने धर्म पर कुछ कहा था, तब भी बांग्लादेश के कट्टरवादियों ने ऐसा ही तांडव मचाया था। वे भी नहीं जानते थे कि वस्तुत: मैंने कहा क्या था। हंगामा मचाने वालों को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि वे किस बात पर हंगामा कर रहे हैं। वे जानना भी नहीं चाहते। उनके सामने सवाल रखने की इजाजत नहीं है। किसी तरह की आलोचना या अध्ययन से भी उनका कोई लेना-देना नहीं है। हद तो यह है कि वे सच भी जानना नहीं चाहते।

ऐसे कट्टरवादियों को जब पता चलता है कि किसी ने उनके धर्म से जुड़ी कोई बात कही है, तो धार्मिक भावना पर आघात लगने का आरोप लगाते हुए वे सड़कों पर उतर पड़ते हैं और समुदाय विशेष को निशाना बनाने के अपने हिंसक और विध्वंसात्मक अभियान में लग जाते हैं। खासकर मुस्लिम देश जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरोध में खड़े हैं, तब यह सवाल पैदा होता है कि यह दुनिया क्या मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों में विभाजित हो जाएगी।

मैंने यह पाया है कि हाल के कुछ वर्षों में बांग्लादेश में अनेक शिक्षकों पर हमला बोला गया है, जिनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से हैं। ऐसा लगता है कि वहां का बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं को अब शिक्षकों के पद पर नहीं देखना चाहता।

हिंदुओं की जमीन और संपत्ति पर पहले ही कब्जा हो चुका है, अब उनको शिक्षकों के सम्माननीय पेशे से हटाने की तैयारी है। स्वख्वन कुमार बसु को अपमानित करने के कुछ ही दिन बाद आशुलिया में एक मुस्लिम छात्र ने हिंदू शिक्षक की क्रिकेट के विकेट से पीट-पीटकर हत्या कर दी।

उस शिक्षक का दोष क्या था? उन्होंने एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार के मामले में उस छात्र को डांटा था। चूंकि वह छात्र स्कूल के मालिक का रिश्तेदार बताया जाता है, ऐसे में, मानना मुश्किल है कि उसे अपने अपराध की सख्त सजा मिलेगी। हालांकि हिंदू शिक्षकों को निशाना बनाने के विरोध में बांग्लादेश में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं, समाज में बढ़ती कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई गई है। लेकिन अच्छी चीजों के बजाय बुरी चीजों का असर और प्रसार ज्यादा होता है।

इसीलिए मानवता के पक्ष में उठी आवाजों की तुलना में सांप्रदायिक विद्वेष और फतवा देने की प्रवृत्ति ही चर्चा में ज्यादा रहेगी। पूरे बांग्लादेश का एक जैसा हाल है। अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं। क्या बांग्लादेश को सौ फीसदी मुस्लिम देश बनाने का लक्ष्य है? यही हाल रहा, तो बांग्लादेश के अफगानिस्तान में बदलने में देर नहीं लगेगी। नाच-गाना, नाटक-सिनेमा सब पर प्रतिबंध लग जाएगा। नारी-विद्वेषी, गणतंत्र-विरोधी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुश्मन पूरे देश पर काबिज हो जाएंगे।

बांग्लादेश में शरिया कानून लागू हो जाएगा। लड़कियों की शिक्षा और नौकरी पर अंकुश लग जाएगा और महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य हो जाएगा। नड़ाइल की घटना के कुछ ही दिन बाद भारत में राजस्थान के उदयपुर में एक नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

दो कट्टरवादी मुस्लिमों ने एक हिंदू दर्जी की सिर्फ इसलिए गला काटकर हत्या कर दी कि उसने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। यही नहीं, हत्यारों ने उस हत्याकांड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया।

भारत में इन दिनों हिंदू-मुस्लिम तनाव बढ़ रहा है। ऐसे माहौल के बीच आईएस की तरह हत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का नतीजा भयंकर हो सकता है, क्या हत्यारे यह नहीं जानते थे? जाहिर है, इसके जरिये भारत में सांप्रदायिक विद्वेष और हिंसा फैलाने की मंशा थी। बेशक उदयपुर की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की प्रतिक्रिया में हिंसा की वैसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन यह भी सच है कि स्थिति सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा।

यही नहीं, भारत के आम मुसलमानों को लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और हिंदुओं के बीच मुस्लिम विद्वेष बढ़ेगा। अभी जो स्थिति है, वही कम डरावनी नहीं है। पूरे उपमहाद्वीप में कट्टरवादियों की भीड़ जलाओ, मार डालो, गिरफ्तार करो, फांसी दो जैसी मांग कर रही है। धार्मिक भावना पर चोट लगने की बात कहते हुए कट्टरवादी लोग सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ही नहीं कर रहे, बल्कि सामने वाले का अस्तित्व मिटा देने की कोशिश तक में लगे हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

धार्मिक रूप से कट्टरवादी जिस तरह मुस्लिम समुदाय में हैं, उसी तरह हिंदू समुदाय में भी हैं। और समाज में कट्टरवाद बढ़ने से हिंदू-मुसलमान, किसी की भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ऐसे में, सबसे ज्यादा मुश्किल उदारवादियों को होती है।

कट्टरवाद के इस व्यापक दौर में वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। सांप्रदायिक घृणा की भावना फैलाने और दंगा-फसाद करने से आम हिंदू-मुसलमानों का कोई भला नहीं होता, इसका फायदा राजनेताओं और राजनीतिक दलों को ही मिलता है।

लेकिन विडंबना यह है कि इसके बावजूद आम लोग कोई सबक नहीं सीखते। कट्टर उन्मादियों की भीड़ के आगे विवश और लाचार होना ही शायद इस उपमहाद्वीप के उदार और चिंतनशील लोगों की नियति है।

अलविदा आबे

सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे अपने मुल्क की राजनीति को बहुत बड़ा मोड़ देना चाहते थे। राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज ही नहीं, वह जापानी लोगों के सोचने का तरीका भी बदल देना चाहते थे। कुछ हद तक वह कामयाब भी रहे। लेकिन शुक्रवार को जब नारा शहर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, तब जापान की राजनीति अचानक एक दूसरे मोड़ पर जा खड़ी हुई। उसकी राजनीति दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से हमेशा ही हिंसा और आक्रामकता जैसी चीजों से दूर रही। हत्या की बात तो खैर सोची भी नहीं जा सकती थी। जापान दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश है, जिसने अपनी संपन्नता और आर्थिक ताकत के बावजूद न सिर्फ एक देश के रूप में हथियारों से दूरी बनाए रखी, बल्कि अपने समाज को भी इससे दूर रखा। जापान में नागरिकों को हथियार खरीदने या अपने पास रखने की इजाजत नहीं है। बंदूकें तो दूर, लोग परंपरागत तलवार भी अपने पास नहीं रख सकते। हिंसा से लगातार इतनी दूरी बनाकर रखने वाले देश में अगर एक सबसे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए, तो यह उस मुल्क के लिए कितना बड़ा सदमा होगा, इसे सिर्फ समझा ही जा सकता है।

हालांकि, ये सब चीजें जिस अतीत और सोच की उपज थीं, शिंजो आबे उसे पूरी तरह बदल देना चाहते थे। कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के दुखद अध्याय ने जापान को जो घाव दिए थे, वह उससे अभी तक उबर नहीं सका। शिंजो आबे जापानी जनमानस को दूसरे विश्वयुद्ध के उस भूत से पूरी तरह मुक्त करना चाहते थे, जो हरदम लोगों के दिलो-दिमाग पर सवार रहता है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जब एक तरह से अमेरिका का वहां कब्जा था, जापान ने अपना संविधान बनाया था, जिसमें यह प्रावधान था कि जापान की अपनी कोई आक्रमणकारी सेना नहीं होगी। आबे इसी को बदलना चाहते थे।

वह एक ऐसा जापान बनाना चाहते थे, जो दुनिया के तमाम देशों की तरह ही एक सैनिक शक्ति भी हो। इसके लिए उन्होंने विश्वयुद्ध के पहले के उस जापानी राष्ट्रवाद को जगाने की कोशिश की, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। लेकिन इसमें वह एक हद के बाद नाकाम रहे। जापान को उसके अतीत के वात, कफ और पित्त से मुक्ति दिलाने का आबे का अभियान यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने चीन से पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की भी कोशिश की। बीजिंग यात्रा पर जाने वाले वह पहले प्रधानमंत्री बने। जापानी साम्राज्य के दौर में वहां की फौज ने जो ज्यादतियां की थीं, उनके लिए शिंजो आबे ने चीन और कोरिया से माफी भी मांगी।

छोटी बचत पर ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत

जयंतीलाल भंडारी

यकीनन इस समय देश में छोटी बचत करने वाले करोड़ों लोग छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली कम ब्याज दर के कारण बढ़ती महंगाई की चुनौती का सामना कर रहे हैं। यह उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह पिछले दो-तीन महीनों में स्थायी जमा (एफडी) के साथ-साथ अन्य ब्याज दरों में वृद्धि हो चुकी है, उसी तरह जुलाई से सितंबर 2022 के लिए छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जब तक महंगाई का दौर बना रहे, तब तक छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कुछ वृद्धि कर दी जाए, तो एक बड़े वर्ग को राहत मिल सकती है।

गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने से कीमतों में तेज वृद्धि से पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी महंगाई तेजी से बढ़ रही है। मई, 2022 में थोक महंगाई दर 15.88 फीसदी और खुदरा महंगाई दर 7.04 फीसदी के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई। ऐसे में रिजर्व बैंक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अब तक 0.90 फीसदी रेपो दर बढ़ा चुका है, बैंक एफडी पर 0.50 फीसदी से अधिक ब्याज दर बढ़ा चुके हैं, बॉन्ड पर यील्ड भी बढ़ता जा रहा है, ऋण महंगे हो रहे हैं, ऋण पर ज्यादा किस्त और ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है और कर्ज के भुगतान की किस्त चूक में भी बढ़ोतरी हो रही है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि हम छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली मौजूदा ब्याज दरों को देखें, तो पाते हैं कि इस समय बचत खाता पर चार फीसदी, एक से तीन साल की एफडी पर 5.5 फीसदी, पांच साल की एफडी पर 6.7 फीसदी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 7.4 फीसदी, एमआईएस पर 6.6 फीसदी, एनएससी पर 6.8 फीसदी, पीपीएफ पर 7.1 फीसदी, किसान विकास पत्र पर 6.9 फीसदी, सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6 फीसदी ब्याज दर देय है। यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.1 फीसदी ब्याज दर की अनुमति दी है। यह चार दशक से अधिक समय में सबसे कम ब्याज दर है। इसका करीब पांच करोड़ ईपीएफ सदस्यों पर असर पड़ा है।

निस्संदेह पिछले दो वर्षों में कोविड-19 की आर्थिक चुनौतियों से लेकर अब तक देश में आम आदमी, नौकरीपेशा वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के सामने एक बड़ी चिंता उनकी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर कम रहने की है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन स्तर हेतु लिए गए सबसे जरूरी हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, कन्ज्यूमर लोन आदि को चुकाने के लिए अधिक ब्याज व किस्तों की राशि में वृद्धि से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

वस्तुत: देश में बचत की प्रवृत्ति के लाभ न केवल कम आय वर्ग के परिवारों के लिए हैं, वरन पूरे समाज व अर्थव्यवस्था के लिए भी हैं। अब भी देश में बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा (सोशल प्रोटेक्शन) की छतरी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों पर देश के उन तमाम छोटे निवेशकों का दूरगामी आर्थिक प्रबंधन निर्भर होता हैं, जो अपनी छोटी बचतों के जरिये जिंदगी के कई महत्वपूर्ण काम निपटाने की व्यवस्था सोचे हुए हैं। मसलन, बिटिया की शादी, सामाजिक रीति-रिवाजों की पूर्ति, बच्चों की पढ़ाई और सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। छोटी बचत योजनाएं रिटायर हो चुके और जमा पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर बुजुर्ग पीढ़ी का सहारा बनती हैं।

करीब 14 वर्ष पूर्व 2008 की वैश्विक मंदी का भारत पर कम असर होने का एक प्रमुख कारण भारतीयों की संतोषप्रद घरेलू बचत की स्थिति को माना गया था। फिर 2020 में महाआपदा कोविड-19 से जंग में भारत के लोगों की घरेलू बचत विश्वसनीय हथियार के रूप में दिखाई दी। नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट (एनएसआई) द्वारा भारत में निवेश की प्रवृत्ति से संबंधित रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां देश के लोगों के लिए छोटी बचत योजनाएं लाभप्रद हैं, वहीं इनका बड़ा निवेश अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभप्रद है। क्या सरकार इस पर गौर करेगी?

आ गया है मानसून। मतलब खूब सारी बारिश और टर्र-टर्र करते मेंढक, मम्मी के हाथ का बना गर्म सूप और कागज की नाव तैराने का समय। ऊपर से सोने पर सुहागा यह कि स्कूल भी अभी बंद ही है, इसलिए तुम्हारे तो वारे-न्यारे हो गए हैं। तुम तो इस मौसम में खूब मस्ती करते हो, ये हमें पता है, पर क्या तुम्हें पता है कि जानवर-पक्षी क्या करते हैं? वो कैसे मजे करते हैं। चलो आज जरा घर से बाहर निकलें और इनकी दुनिया में चलें...

मानसून में ये भी गाते गुनगुनाते नहाते हैं..

यूं तो बारिश में ज्यादातर जानवर और पक्षी छांव वाली जगह की तलाश में रहते हैं, जहां उन पर पानी न गिरे। इसके लिए वे किसी पेड़ के तने, गुफा, पत्ते के नीचे या जमीन के नीचे चले जाते हैं। लेकिन कई जानवर इस बारिश को खूब पसंद करते हैं। खासकर कुछ खास किस्म की चिड़िया गाना गाती हैं तो कुछ पंख फैलाकर नहाती हैं। बारिश के समय मैना, कोयल खूब गाना गाती हैं। चिड़ियों को बारिश खूब पसंद होती है। वो पेड़ की डाली पर बैठकर बारिश का मजा लेती हैं। पत्तों से टपकता पानी उन्हें खूब पसंद है। लेकिन कई तरह की चिड़िया इस मौसम के आने से पहले दूसरे इलाकों में कूच कर जाती हैं। इनमें व्हाइट रप्ड मनाकिंस खास है। अमेरिका में रहने वाली ये चिड़िया फल खाती है और दो-तीन घंटे से अधिक समय तक भोजन के बिना नहीं रह सकती। जैसे ही बारिश का मौसम आता है ये दूसरे इलाकों की ओर चली जाती हैं।

ऐसे बचाओ अपने पेट्स को

बारिश के समय तुम यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पेट्स भीगें नहीं। अगर वो भीग भी गए हैं तो उन्हें तुरंत पोंछ दो। अगर उन्हें ठंड लग रही है तो किसी कंबल से ढंककर रखो। जैसे ही बारिश बंद हो तो उन्हें घुमाने कहीं बाहर ले जाओ। उनके साथ खूब खेलो, जिससे वे सुस्त न पड़ें। उनके फर और पंजों को साफ करते रहो। इस मौसम में सबसे ज्यादा जानवर बीमार होते हैं, इसलिए तुम उन पर नजर रखो। अगर उन्हें जलन-खुजलाहट हो रही है या बाल झड़ने लगे हैं तो यह इन्फेक्शन के पनपने की निशानी है। समय से वेक्सिनेशन करवाना जरूरी है।

मौसम बदलेगा, ये पहले से जान लेते हैं: भारी बारिश या तूफान आने से पहले ब्लैक कोकाटूस पहाड़ों से नीचे आना आरंभ कर देते हैं। ऐसा ये सुबह के समय करते हैं।

बिल्लियां अपने पैरों को चाटती हैं और उससे अपनी आंखों को साफ करती हैं। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली के कान काफी तेज होते हैं और उन्हें मौसम बदलने से पहले ही कुछ ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जिससे उनमें यह बदलाव आ जाता है।

गाय का बछड़ा यदि ज्यादा एक्टिव दिख रहा हो तो इसका मतलब है कि बारिश आने वाली है। बछड़ा ऐसे में अपनी आंखों क ो

खुजलाना आरंभ करता है। अगर कुत्ता अपनी पीठ के बल सोने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मौसम बदल सकता है। अगर मेंढक चिल्लाने लगें तो मान लें कि 24 से 48 घंटे में बारिश गिरेगी। तोते बारिश होने से पहले खास तरह की आवाजें निकालना आरंभ कर देते हैं। कछुए अगर नदी को छोड़कर मैदानी इलाकों की ओर आएं तो समझ लीजिए कि बारिश या बाढ़ आने वाली है।

तुम्हारे लिए मस्ती का समय है ये...

स्कूल अभी कुछ दिन पहले ही खुले हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। मतलब फुल टू मस्ती और धमाल करने का समय है ये। तुम बारिश में खूब नहा सकते हो, खेल सकते हो और चाहो तो घर की खिड़की से इसके नजारे देख सकते हो।

पानी में छप-छप करना, दोस्तों को भिगोना, उन्हें छींटे मारना, नाव बनाकर तैराना कितना मजेदार होगा ना। हल्की बारिश में फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो और मस्ती करो। अगर मां घर से न निकलने दें तो पेंटिंग बनाओ या सूप पियो।

क्या करते हैं जानवर

तोता चुप रहता है और कोई जगह ढूंढकर वहां छिप जाता है। गिलहरी और चुहिया गर्म जगह की तलाश करते हैं और वहां से छिपकर बारिश देखते हैं। मेंढ़क, कछुए और मछली तालाब या झील के नीचे के भाग में स्थित पत्थरों में शरण लेते हैं। रेंगने वाले जीवों जैसे सांप आदि की खासियत होती है उनकी चमड़ी। चमड़ी पर प्रोटीन होता है, जिसे केरेटिन कहा जाता है। ये उनकी त्वचा को वॉटरप्रूफ बना देता है, इसलिए ये खूब नहाते हैं। ओरंगुटान किसी पेड़ के पत्तों से अपने सिर को ढंककर बैठ जाता है। पीले रंग की चिडिया अमेरिकन गोल्डफिंचेस जरा सी देर भी गीला होकर नहीं रह सकती। बारिश शुरू होते ही वह सूखी जगह की तलाश कर वहां छिप जाती है। मोर बारिश शुरू होने से पहले नाचना शुरू कर देता है। मॉरनिंग डव्स को नहाना पसंद होता है। कठफोड़वा भी खूब नहाता है। बारिश के समय मेंढक तेज आवाजें निकालता है। तोता बारिश बंद होने के बाद एक डाली से दूसरी डाली तक आता-जाता है और नाचता है।

मानसून बोलो या काल वर्षा

मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द 'मौसिम' से बना है। केरल में मानसून को 'काल वर्षा' कहा जाता है। 'मानसून' उन मौसमी पवनों को कहते हैं, जो ठंड में महाद्वीपों से महासागरों की ओर और गर्मी में महासागरों से महाद्वीप की ओर चलती हैं।

बारिश में भीगो पर...

बारिश में भीगने में सभी को मजा आता है। चुभती-जलती गर्मी से राहत मिलती है, प्रकृति और भी सुंदर हो जाती है। जगह-जगह बहते झरने, नदियां कितने सुंदर लगते हैं। वैसे तो मम्मी-पापा भी बारिश को पसंद करते हैं, पर जब बारी बच्चों की आती है तो मम्मी ज्यादा देर बारिश में नहाने नहीं देतीं। जल्दी से घर में आ जाओ, बारिश में मत भीगो, बस इसी बात की रट लगाये रहती हैं। उनका कहना सही भी है, क्योंकि बारिश बच्चों के लिए बीमारियों का कारण भी बन सकती है। हां, अगर तुम इन बातों को ध्यान में रखो तो तुम बारिश का मजा भी ले सकते हो और बीमार भी नहीं पड़ोगे। इस मौसम में सबसे ज्यादा मच्छर पैदा होते हैं, जो कई बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए घर में पानी इकट्ठा मत होने दो। इसके लिए तुम घर में नीम की सूखी पत्तियों का धुंआ कर सकते हो। मानसून में पीने के पानी में अक्सर गंदगी आ जाती है, जो टायफाइड, कॉलरा जैसी बीमारियां फैलाती है। इसलिए पानी उबालकर ही पीएं। बाहर का खाना न खाएं। बारिश के पानी में ज्यादा देर तक मत रहो। इससे तुम्हें स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए तुम रेनकोट, रेनबूट पहनो और छाता लेकर ही निकलो। जब भी भीगो तो जल्दी से कपड़े बदलो। इस समय गटर या मेनहोल्स के पास मत जाओ, क्योंकि ये सभी ओवरफ्लो होते हैं। मानसून में सर्दी-जुकाम और खांसी हो जाती है। इसलिए मम्मी जो दें वो ही खाओ। नाखूनों को काटकर रखो, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इन नाखूनों से ही पेट के अंदर जाती हैं। इस मौसम में तुम्हें बार-बार हाथ धोने चाहिये। अगर बारिश में तुम्हारे मोजे गीले हो जाएं तो उन्हें उतार दो, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर तुम्हारे घर में एसी लगा है तो नहा कर सीधे उस कमरे में मत जाना, बीमार पड़ सकते हो। गीले बिजली के तारों को मत छूना और न ही उन पर फंसी कोई चीज लोहे के डंडे से निकालने की कोशिश करना।

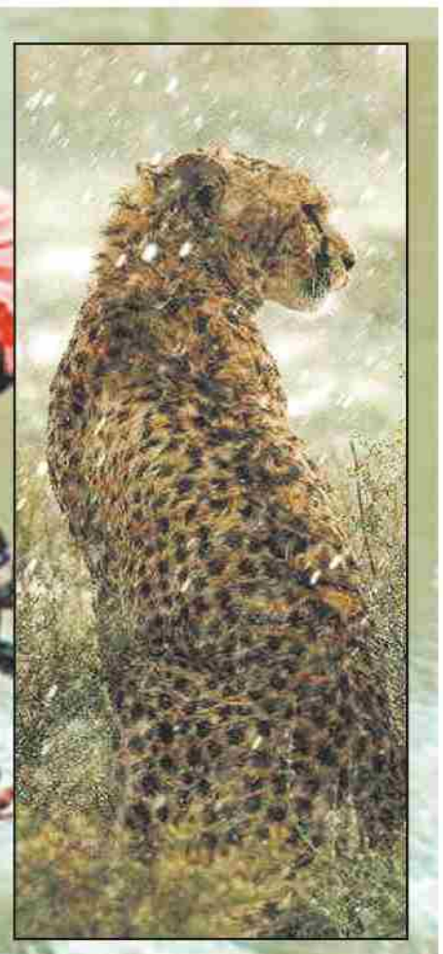

जानो आइसक्रीम की हिस्ट्री

बच्चों! आइसक्रीम हर किसी को ललचाती है। आज बाजार में आइसक्रीम वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनऐपल आदि के स्वाद के साथ कोन, कप, स्टिक आदि के आकर्षक पैकेज में मौजूद है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर तरह-तरह की वेरायटी वाली आइसक्रीम बनी कैसे, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? आइए जानें इस बारे में..

वैसे यह निश्चित रूप से मालूम नहीं है कि सबसे पहले आइसक्रीम कैसे बनी और इसकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन एक किंवदंती के अनुसार, लगभग दो हजार साल पहले रोमन सम्राट नीरो ने अपने गुलामों से कहा था कि वे पास के पहाड़ों से बर्फ ले आयें। नीरो ने उस बर्फ में फलों का रस, शहद आदि मिलाया और उसका आनंद लिया. इसे ही आइसक्रीम की शुरुआत माना जा सकता है। समय बीतने के साथ लोग बर्फ में अन्य स्वादिष्ट चीजें मिलाकर खाने लगे और सन् 1600 तक आइसक्रीम काफी लोकप्रिय हो युकी थी। इसके बाद लोग अनेक प्रकार के प्रयोग करके इसे नया-नया रूप, आकार व स्वाद देकर और लोकप्रिय बनाते चले गये। एक बार पार्टियों में वेटर का काम करने वाले रॉबर्ट ग्रीन नामक व्यक्ति ने मजबूरीवश एक प्रयोग कर डाला। उस समय क्रीम और काबरेनेटेड पानी मिला कर एक पेय बनाया जाता था जो कई दशकों तक खासा लोकप्रिय रहा था। एक पार्टी में उस पेय के लिए क्रीम कम पड़ गई। ग्रीन ने उसकी जगह वनीला आइसक्रीम डाल दी। आइसक्रीम एक फोम के रूप में गिलास में ऊपर तक भर गई और वह घोल काफी स्वादिष्ट बन पड़ा था और जल्दी ही वह लोकप्रिय हो गया। इसे आइसक्रीम सोडा के नाम से पुकारा जाने लगा। इसी तरह के मजबूरीवश किये प्रयोगों ने अन्य प्रकार की आइसक्रीम्स को जन्म दिया।

संडे आइसक्रीम

स्मिथसन नामक व्यक्ति के पास एक छोटा-सा रेस्त्रं था, जिसमें लोग आइसक्रीम खाने अक्सर आते थे. 1890 के एक रविवार के दिन उसके रेस्त्रं में आइसक्रीम कम पड़ने लगी और दूसरी चीजें, जैसे फल, विभिन्न प्रकार की चॉकलेटें, क्रीमें आदि काफी थीं। रविवार को आइसक्रीम की आपूर्ति नहीं होती थी इसलिए स्मिथसन ने आइसक्रीम की मात्र कम कर दी तथा उसके ऊपर फल, चॉकलेट सिरप और दूसरी गाढ़ी क्रीम डालना प्रारंभ कर दिया। जब ग्राहकों ने इसकी तारीफ करना प्रारंभ कर दिया तो उसने इस आइसक्रीम का नाम संडे आइसक्रीम रख दिया। अब वह हर रविवार को संडे आइसक्रीम देने लगा। धार्मिक कारणों से कुछ लोगों द्वारा संडे नाम का विरोध करने पर स्मिथसन ने संडे आइसक्रीम में संडे की स्पेलिंग बदल डाली।

कोन वाली आइसक्रीम

कुरकुरे कोन में आइसक्रीम खाने का अलग ही आनंद है। इसकी शुरुआत भी मजबूरी में ही हुई। 1904 में सेंट लुई मेले में दो व्यक्ति खाने की वस्तुओं के काऊंटर पर अगल-बगल खड़े थे। एक पेपर की प्लेटों में आइसक्रीम बेच रहा था और दूसरा वेफर पर (पेस्ट्री जैसा लगने वाला) जिसके ऊपर चीनी के दाने चिपके हुए थे। अगस्त का महीना था और लोग धड़ाधड़ आइसक्रीम ले रहे थे। वेफर बेचने वाला मुंह ताक रहा था। तभी अचानक कागज की प्लेटें कम पड़ गईं और आइसक्रीम वाले को लगा कि अब उसे अपना काऊंटर बंद करना पड़ेगा। तभी वेफर बेचने वाला उसकी मदद के लिए आगे आया। उसने वेफल से कोन बनाया और दोनों उसमें आइसक्रीम भर कर बेचने लगे। लोगों को कुरकुरा वेफ र आइसक्रीम के साथ बहुत भाया तथा अब वह खूब बिकने लगा। 1920 तक एक-तिहाई आइसक्रीम कोन में बिकने लगी।

चॉकलेट आइसक्रीम

एक दिन क्रिश्चियन नेल्सन नामक व्यक्ति अमेरिका के आयोवा में स्थित अपनी दुकान में आइसक्रीम व चॉकलेट बेच रहा था। तभी एक बालक हाथ में सिक्के लिए दुकान में आया और आइसक्रीम की फरमाइश की। फिर उसने इरादा बदल दिया और चॉकलेट की फरमाइश कर डाली। नेल्सन को लगा कि यह बालक तभी संतुष्ट हो पायेगा जब उसे दोनों स्वाद मिलेंगे। उसने आइसक्रीम की एक स्लाइस काटी तथा उसके दोनों ओर चॉकलेट की पतली परत चिपका दी और तभी चॉकलेट आइसक्रीम की खोज हो गयी। अब वह नयी चॉकलेट वाली आइसक्रीम जमाने लगा। उसने इस दिशा में अनेक प्रयोग भी कर डाले ताकि चॉकलेट उसकी आइसक्रीम से भली प्रकार चिपक जाये। उसे सफलता आसानी से नहीं मिल रही थी। तभी उसको एक सेल्समैन ने सलाह दी कि वह कोको बटर का प्रयोग करे। अब नेल्सन ने नये सिरे से प्रयोग प्रारंभ कि ये। 1920 में एक रात उसने आइसक्रीम की एक स्लाइस चॉकलेट के मिश्रण में डाली। कुछ देर बाद चॉकलेट ठंडा होकर आइसक्रीम के चारों ओर जम गया। इसके साथ ही चॉकलेट लगी आइसक्रीम खासी लोकप्रिय हो गई।

पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम, सरकार ने गैस कीमतों में की 235 फीसदी वृद्धि

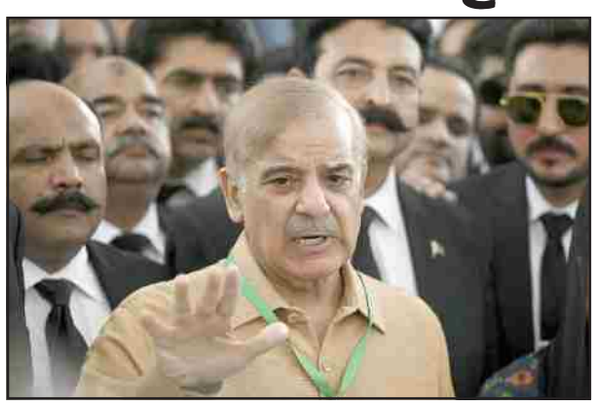

इस्लामाबाद, 09 जुलाई (एजेन्सी)। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार भी जनता को महंगाई से राहत दिलाने में नाकामयाब साबित हो रही है। आर्थिक मंदहाली की गर्त में डूब चुके पाकिस्तान की जनता ईंधन की कीमतों में बेताहाशा वृद्धि से बदहाल हो रही है। शहबाज सरकार ने बेचारी जनता पर महंगाई का नया बम फोड़ते हुए 1 जुलाई से प्राकृतिक गैस (एलपीजी) की कीमतों में 43 प्रतिशत से 235 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि के जरिए अधिकांश घरेलू और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं से सरकार 660 अरब पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) वसूलेगी।

देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच बीते 11 महीनों में पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज 15.3 फीसदी बढ़ गया है। डॉन की रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के हवाले से बताया गया है कि जून 2021 में सरकार का कुल कर्ज 38.704 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो मई में बढ़कर 44.638 ट्रिलियन हो गया।

पेट्रोलियम राज्यमंत्री मुसादिक मलिक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'लगभग आधे घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कीमतों में उछाल से बचाया गया है, लेकिन उच्च वर्ग पर बोझ काफी बढ़ गया है।' यह फैसला पाकिस्तान की कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने लिया। ईसीसी ने उन घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक बोझ डाला, जिनकी मासिक गैस खपत चार क्यूबिक मीटर तक है।

अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, उन्हें अब पांच क्यूबिक मीटर गैस उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा गया है। उनके लिए मौजूदा कीमतों से 154 प्रतिशत की वृद्धि होगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा, 'ईसीसी ने पीकेआर 100 की प्रस्तावित दरों के मुकाबले निर्यात और गैर-निर्यात उद्योग (कैप्टिव पावर) के लिए गैस दरों को और कम करने के निर्देश के साथ उपभोक्ता गैस बिक्री कीमतों में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी।' पेट्रोलियम राज्यमंत्री ने कहा कि कीमतों में वृद्धि का उद्देश्य गैस क्षेत्र में सर्कुलर लोन को बढ़ाने से रोकना है. मुसादिक ने कहा, 'कीमतों में अधिक वृद्धि का उद्देश्य इस वित्तीय वर्ष में गैस क्षेत्र में ऋण की बढ़त रोकना है।'

बता दें पाकिस्तान में 2018 से ऊर्जा कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया में गैस की कीमतों में इजाफा किया है। वित्तीय क्षेत्र, बजट और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इससे भार पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, मूल्य समायोजन में विलंब, डिफर्ड पेमेंट, प्रमुख निवेश को रोके रखना और गैर-लक्षित सब्सिडी देने सहित कई कारण हैं। देश में बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच बीते 11 महीनों में पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज 15.3 फीसदी बढ़ गया है।

डॉन अखबार ने बताया है कि जून 2021 में सरकार का कुल कर्ज 38.704 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो मई में बढ़कर 44.638 ट्रिलियन रुपए हो गया। पाकिस्तान सरकार का घरेलू कर्ज और देनदारियां जून 2021 में जहां 26.968 ट्रिलियन रुपए थीं, वहीं मई 2022 में यह बढ़कर 29.850 ट्रिलियन रुपए हो गईं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, घरेलू लोन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक गंभीर समस्या का कारण बनता है क्योंकि अधिकांश राजस्व का उपयोग ऋणों की अदायगी के लिए किया जाता है।

राष्ट्रपति राजपक्षे के आधिकारिक आवास में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी

कोलंबो, 09 जुलाई (एजेन्सी)। श्रीलंका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को मध्य कोलंबो के कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में अवरोधकों को हटाकर उनके (राष्ट्रपति के) आधिकारिक आवास में घुस गए। सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में दो पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 30 लोग घायल हो गए।

कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में श्रीलंका का ध्वज और हेलमेट थे। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर फोर्ट इलाके में एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारी देश में गंभीर आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

राजपक्षे पर मार्च से ही इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। वह अप्रैल में प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कब्जा करने के बाद से ही राष्ट्रपति आवास को अपने आवास तथा कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, शनिवार के विरोध प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रपति को शुक्रवार को उनके आवास से बाहर ले जाया गया था। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति को कहां ले जाया गया है, इस बारे में पता नहीं चल सका है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के कार्यालय और आधिकारिक आवास दोनों पर कब्जा कर लिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें कीं तथा गोलियां चलायीं, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी अवरोधकों को हटाकर राष्ट्रपति आवास में घुस गए।

उनके अपने सांसदों के एक समूह ने उन्हें एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे पद छोड़ने और एक नया प्रधानमंत्री और एक सर्वदलीय सरकार गठित करने का आग्रह किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मुताबिक, एक वीआईपी काफिला कोलंबो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया है, जहां श्रीलंका एयरलाइंस का एक विमान खड़ा था।

इस बीच, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने जनता के प्रदर्शन से देश में पैदा हुए संकट पर चर्चा करने के लिए शनिवार को राजनीतिक दल के नेताओं की तत्काल बैठक बुलायी। विक्रमसिंघे के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने पार्टी की तत्काल बैठक बुलायी है और स्पीकर से तत्काल संसद का सत्र बुलाने का अनुरोध किया है।

सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण मई में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था।

प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास की दीवारों पर चढ़ गए और वे अंदर ही हैं। हालांकि, उन्होंने किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही किसी तरह की हिंसा की है।

इस बीच, प्रदर्शनों के दौरान दो पुलिस अधिकारियों समेत कम से कम 30 लोग घायल हो गए और उन्हें कोलंबो में नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले, पुलिस ने राष्ट्रपति के आवास की ओर जाने वाली दो सड़कोंचैथम स्ट्रीट और लोटस रोड पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन वे रुके नहीं।

प्रदर्शनकारियों की गाले, कैंडी और मतारा शहरों में रेलवे प्राधिकारियों से भी झड़प हुई और उन्होंने प्राधिकारियों को कोलंबो के लिए ट्रेन चलाने पर विवश कर दिया। इलाके में पुलिस, विशेष कार्य बल और सेना की बड़ी टुकड़ियों को तैनात किया गया है।

होल कंट्री टू कोलंबो आंदोलन के आयोजकों ने कहा कि लोग कोलंबो फोर्ट में प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होने के लिए उपनगरों से पैदल निकल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं दे देते हैं। इससे पहले श्रीलंका पुलिस ने शीर्ष वकीलों के संघ, मानवाधिकार समूहों और राजनीतिक दलों के लगातार बढ़ते दबाव के बाद शनिवार को सात संभागों से कर्फ्यू हटा लिया।

पुलिस के मुताबिक पश्चिमी प्रांत में सात पुलिस संभागों में कर्फ्यू लगाया गया था जिसमें नेगोंबो, केलानिया, नुगेगोडा, माउंट लाविनिया, उत्तरी कोलंबो, दक्षिण कोलंबो और कोलंबो सेंट्रल शामिल हैं। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात नौ बजे से अगली सूचना तक लागू किया गया था।

श्रीलंका के बार एसोसिएशन ने कर्फ्यू का विरोध करते हुए इसे अवैध और मौलिक अधिकारों का हनन करार दिया था।

बार एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, इस तरह का कर्फ्यू स्पष्ट रूप से अवैध है और हमारे देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनकी सरकार की विफलता को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग ने कर्फ्यू को मानवाधिकारों का घोर हनन बताया है। गौरतलब है कि 2.2 करोड़ की आबादी वाला देश श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस बीच, श्रीलंका में अमेरिकी राजदूत जूली चुंग ने शुक्रवार को देश की सेना और पुलिस से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने का आग्रह किया।

उन्होंने ट्वीट किया, हिंसा कोई जवाब नहीं है..अराजकता और बल प्रयोग से अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी या राजनीतिक स्थिरता नहीं आयेगी, जिसकी अभी श्रीलंका को जरूरत है।

श्रीलंका में संकट गहराया, पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने दिया इस्तीफा

कोलंबो, 09 जुलाई (एजेन्सी)। श्रीलंका में आर्थिक हालात से त्रस्त जनता ने शनिवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। वहीं राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर भाग गए हैं। इसी बीच, श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि आज पार्टी नेताओं की बैठक में सभी नागरिकों की सुरक्षा समेत सरकार की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय सरकार बनाने का फैसला लिया गया। मैं इस फैसले को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं।

बता दें कि, इससे पहले स्पीकर के घर जूम पर हुई नेताओं की बैठक में राष्ट्रपति और पीएम के पद छोड़ने की पेशकश की गई थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को कहा कि वह इस्तीफा देने के इच्छुक हैं ताकि देश में सर्वदलीय सरकार गठित करने के लिये रास्ता बन सके। प्रधानमंत्री के मीडिया प्रभाग ने कहा कि सर्वदलीय सरकार बनने और संसद में बहुमत साबित होने के बाद वह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे।

उनके कार्यालय ने कहा कि विक्रमसिंघे तब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। विक्रमसिंघे ने पार्टी नेताओं से कहा कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पद छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं कि इस सप्ताह से देशव्यापी ईंधन वितरण दोबारा शुरू किया जाना है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक इस सप्ताह देश का दौरा करने वाले हैं और आईएमएफ के लिए ऋण निरंतरता रिपोर्ट को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाना है।

श्रीलंका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को मध्य कोलंबो के कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में अवरोधकों को हटाकर उनके (राष्ट्रपति के) आधिकारिक आवास में घुस गए। सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में दो पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 30 लोग घायल हो गए। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में श्रीलंका का ध्वज और हेलमेट थे।

सूत्रों के अनुसार, शनिवार के विरोध प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रपति को शुक्रवार को उनके आवास से बाहर ले जाया गया था। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति को कहां ले जाया गया है, इस बारे में पता नहीं चल सका है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के कार्यालय और आधिकारिक आवास दोनों पर कब्जा कर लिया है।

यूक्रेन ने भारत समेत कई देशों में अपने राजदूतों को किया बर्खास्त

कीव, 09 जुलाई (एजेन्सी)। रूस की ओर से शुरू की गई जंग का सामना कर रहे यूक्रेन ने शनिवार को जर्मनी, भारत समेत कई देशों में अपने राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एक आदेश में जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी में यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त करने की घोषणा की गई है हालांकि, इस कदम के पीछे का कोई वजह नहीं बताया गया है। भारत उन देशों में शामिल है जिसने रूस की ओर से यूक्रेन पर किए हमले का खुले रूप से विरोध नहीं किया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की ओर से इन राजदूतों के हटाए जाने के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है। यह भी नहीं बताया गया है कि क्या इन अधिकारियों को कोई और जिम्मेदारी तो नहीं दी जाएगी। ज़ेलेंस्की ने अपने राजनयिकों से यूक्रेन के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन और सैन्य सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

जर्मनी के साथ कीव के संबंध, जो रूसी ऊर्जा आपूर्ति और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐसे में यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला हो सकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के बाद से जर्मनी को अपना गैस भंडार भरने में दिक्कत हो रही है। जंग की वजह से रूस की ओर से गैस सप्लाई में दिक्कत आ रही है। ऐसे में जर्मनी बिजली उत्पादन के लिए कोयले की तरफ रुख कर रहा है।

जर्मनी और कीव कनाडा में रखे गए एक जर्न निर्मित टरबाइन को लेकर भी आमने-सामने हैं। जर्मनी चाहता है कि ओटावा यूरोप को गैस पंप करने के लिए रूसी प्राकृतिक गैस की दिग्गज कंपनी गजप्रोम को वो टरबाइन लौटा दें लेकिन, यूक्रेन इसका विरोध कर रहा है। कीव ने कनाडा से टर्बाइन रखने का आग्रह करते हुए कहा है कि इसे रूस को भेजना मास्को पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे का पार्थिव शरीर लाया गया टोक्यो, अंतिम संस्कार 12 को

टोक्यो, 09 जुलाई (एजेन्सी)। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधान मंत्री रहने वाले शिंजो आबे की आगामी चुनावों के प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या करने के एक दिन बाद, उनके शरीर को पश्चिमी जापान के नारा शहर से टोक्यो ले जाया गया ।67 वर्षीय नेता को एक पूर्व सैनिक ने घर में बनी बंदूक से दो बार गोली मारी थी।

नारा आपातकालीन सेवा विभाग ने शुक्रवार को कहा कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वह गर्दन के दाहिने हिस्से और बाएं हंसली पर घायल हो गए थे और कोई महत्वपूर्ण लक्षण नहीं थे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आबे की पत्नी अखी आबे उनके शव को टोक्यो ले आई हैं। आबे का अंतिम संस्कार कथित तौर पर 12 जुलाई को होगा।

पुलिस ने घटनास्थल पर ही हमलावर को पकड़ लिया। वह जापान की नौसेना का पूर्व सदस्य है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल देसी बंदूक बरामद कर ली और बाद में उसके अपार्टमेंट में कई बंदूकें बरामद की गयी। रविवार को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले आबे की हत्या ने देश को सकते में डाल दिया है और इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या आबे की सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त थे।

अमेरिका में गर्भपात पर रोक के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, जो बाइडेन ने किया हस्ताक्षर

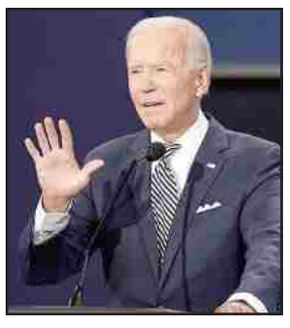

वाशिंगटन, 09 जुलाई (एजेन्सी)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में गर्भपात पर रोक लगाने के शासकीय आदेश पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि, उन्होंने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए लोगों से इस फैसले से निराश न होने की अपील की। बाइडेन ने कहा कि गर्भपात के अधिकार को कायम रखने का सबसे त्वरित तरीका एक राष्ट्रीय कानून पारित करना है। इसके लिए मतदान कराने की चुनौती है। अच्छी बात यह है कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं।

शासकीय आदेश पर बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद न्याय मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय को महिलाओं को गर्भपात कराने या उन राज्यों की यात्रा करने से रोकने का अधिकार मिल गया है, जहां गर्भपात कराने पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं है। अमेरिका के कुछ राज्यों में अब भी गर्भपात की अनुमति है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तों का पालन करना होगा।

गौरतलब है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया था। अदालत का फैसला अधिकतर अमेरिकियों की इस राय के विपरीत था कि 1973 के रो बनाम वेड फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए जिसमें कहा गया था कि गर्भपात कराना या न कराना, यह तय करना महिलाओं का अधिकार है। इससे अमेरिका में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार मिल गया था।

प्रदर्शनकारियों के सामने झुके गोटबाया राजपक्षे, 13 जुलाई को देंगे इस्तीफा

कोलंबो, 09 जुलाई (एजेन्सी)। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने शनिवार रात को यह जानकारी दी। अभयवर्धने ने शनिवार शाम को हुई सर्वदलीय नेताओं की बैठक के बाद उनके इस्तीफे के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस फैसले के बारे में संसद अध्यक्ष को सूचित किया। अभयवर्धने ने बैठक में लिए गए निर्णयों पर राजपक्षे को पत्र लिखा।

पार्टी के नेताओं ने राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के तत्काल इस्तीफे की मांग की थी जिससे कि संसद का उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने तक अभयवर्धने के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त हो सके। विक्रमसिंघे पहले ही इस्तीफा देने की इच्छा जता चुके हैं। राजपक्षे ने अभयवर्धने के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि वह 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे। शनिवार के विरोध प्रदर्शनों से पहले शुक्रवार को अपने आवास से निकलने के बाद राजपक्षे के ठिकाने का पता नहीं चला है।

प्रदर्शन के दौरान हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था। राजपक्षे मार्च से इस्तीफे के दबाव का सामना कर रहे थे। वह राष्ट्रपति भवन को अपने आवास और कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि प्रदर्शनकारी अप्रैल की शुरुआत में उनके कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कब्जा करने पहुंच गए थे।

श्रीलंका एक अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। 2.2 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश सात दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी है, जिससे देश ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के जरूरी आयात के लिए भुगतान कर पाने में असमर्थ हो गया है।

नर्सिंग होम पर हमले के लिए रूस के साथ यूक्रेनभी जिम्मेदार : संयुक्त राष्ट्र

वाशिंगटन, 09 जुलाई (एजेन्सी)। रूस द्वारा फरवरी के अंत में यूक्रेन पर आक्रमण किये जाने के करीब दो सप्ताह बाद क्रेमलिन समर्थित विद्रोहियों ने पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र के एक नर्सिंग होम पर हमला किया था। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले के लिए रूस के साथ-साथ यूक्रेन को भी समान रूप से जिम्मेदार ठहराया है।

इस हमले की वजह से कई मरीज बिना बिजली-पानी के नर्सिंग होम की इमारत में फंस गए थे।

उल्लेखनीय है कि 11 मार्च को यूक्रेन की राजधानी कीव से 580 किलोमीटर दक्षिण पूर्व के गांव स्टारा क्रास्न्यांका स्थित नर्सिंग होम पर हमला किया गया था। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस पर करीब 50 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया था।

इस हमले को युद्ध के दौरान बरती गई क्रूरता बताया गया और यूक्रेन के अधिकारियों ने घटना के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की एक नयी रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले के लिए यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं समान रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमले से कुछ दिन पहले उन्होंने नर्सिंग होम की इमारत के अंदर से मोर्चा संभाला था जिसने इमारत को दुश्मन सेना के निशाने पर लाने का काम किया।

संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नर्सिंग होम में मौजूद 71 मरीजों में कम से कम 22 बचने में सफल रहे, लेकिन मृतकों की वास्तविक संख्या अब भी अज्ञात है।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय अपनी रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि यूक्रेनी सैनिक या मॉस्को समर्थित अलगाववादी लड़ाकों में से किसने युद्ध अपराध किया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि नर्सिंग होम पर किया गया हमला मानवाधिकार कार्यालय के लिए चिंता का विषय है।

इस युद्ध में अमेरिका, यूक्रेन का सहयोग कर रहा है और वह रूस पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाता रहा है।

अमेरिका रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी और कई अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधों की जांच का अनुभव रखने वाले डेविड क्रेन ने कहा कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन को भी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने नर्सिंग होम में रहने वालों और कर्मचारियों को वहां से नहीं निकालकर संभवत: सैन्य संघर्ष के नियमों का उल्लघंन किया है।

क्रेन ने कहा, मौलिक सिद्धांत है कि आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। भले कोई भी कारण हो। लेकिन यूक्रेनी सेना ने उन लोगों को वहां रखा जो प्राणों के लिए घातक क्षेत्र था। आप ऐसा नहीं कर सकते।

रोहित के रणबांकुरों ने लिया टेस्ट की हार का बदला, लगातार दूसरे टी20 में रौंद जीती सीरीज

बर्मिंघम, 09 जुलाई (एजेन्सी)। भारत ने इंग्लैंड को एजबेस्टन टी20 में 49 रनों से हराकर तीन मैच की इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया ने साउथहैंप्टन में मेजबानों को 50 रनों से रौंदा था। बात दूसरे टी20 की करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रवींद्र जडेजा के नाबाद 46 रनों के दम पर 170 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए डेब्यूटंट ग्लीसन ने तीन तो क्रिस जॉर्डन ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी इंग्लिश टीम 121 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार ने सबसे अधिक तीन विकेट ली वहीं, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल को 2-2 विकेट मिले। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने यह लगातार 14वां मुकाबला जीता है।

भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ विकेटकीपर ऋषभ पंत ने पारी का आगाज किया। पारी के पहले ओवर में डेविड विली की चौथी गेंद पर जेसन रॉय ने रोहित का कैच टपकाया और भारतीय कप्तान ने ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर जले पर नमक छिड़का। उन्होंने पारी के तीसरे ओवर में इस गेंदबाज का स्वागत फिर से छक्का लगाकर किया जबकि पंत ने इसी ओवर में दो चौके जड़े। दोनों ने इसके बाद मोईन अली के खिलाफ चौके जड़े।

पांचवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आये पदार्पण कर रहे ग्लीसन का स्वागत भी रोहित ने चौके से किया लेकिन इस गेंदबाज ने भारतीय कप्तान को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच कराकर अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला विकेट झटका। उन्होंने इस तरह रोहित और पंत की 49 रन की साझेदारी को खत्म किया।

पंत ने इसके बाद मोईन के खिलाफ छठे ओवर में छक्का और चौका जड़ा जिससे पावरप्ले में भारत का स्कोर एक विकेट पर 61 रन हो गया। ग्लीसन ने अपने अगले ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर पूर्व कप्तान विराट कोहली (एक रन) और पंत को चलता किया। इस तरह उन्होंने चार गेंद के अंदर तीन विकेट लिये।

सूर्यकुमार यादव और पिछले मैच में अर्धशतक जड़ने वाले हरफनमौला हार्दिक पंड्या ने इसके बाद संभल कर बल्लेबाजी की लेकिन दोनों क्रीज पर समय देने के बाद 11वें ओवर में क्रिस जॉर्डन की लगातार गेंदों पर आउट होकर पवेलियन लौटे। सूर्यकुमार ने 11 गेंद में 15 जबकि हार्दिक ने 15 गेंद में 12 रन बनाये। अब भारत का स्कोर 11 ओवर में 89 रन पर पांच विकेट हो गया। लगातार दो विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम बैकफुट पर थी लेकिन जडेजा ने बीच-बीच में चौका लगाकर टीम की रनगति को बनाये रखा। उन्हें दिनेश कार्तिक का अच्छा साथ मिल रहा था लेकिन 16वें ओवर में कार्तिक 17 गेंद में 12 रन बनाकर रन आउट हो गये। लिविंगस्टोन के इस ओवर में हालांकि जडेजा और हर्षल पटेल ने एक - एक चौका लगाया।

हर्षल ने 17वें ओवर में जॉर्डन के खिलाफ छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने ग्लीसन को कैच थमा दिया। उन्होंने छह गेंद में 13 रन बनाये। जडेजा ने इसके बाद 19वें और 20वें ओवर में एक-एक चौका लगाकर टीम के स्कोर को 170 तक पहुंचाया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने जेसन रॉय को आउट कर झटका दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में भुवी ने बटलर को भी अपने जाल में फंसाया। सलामी बल्लेबाजों के फ्लॉप होने के बाद इंग्लैंड लगातार अंतराल में विकेट खोता रहा और हर एक बल्लेबाज तेज से रन बनाने के प्रयास में आउट होता रहा। इंग्लिश टीम के लिए मोइन अली ने सबसे अधिक 35 रनों की पारी खेली।

एलेना रिबाकिना ने जबूर को हराकर रचा इतिहास

विंबलडन, 09 जुलाई (एजेन्सी)। एलेना रिबाकिना ने शनिवार को विंबलडन फाइनल में खिताबी मुकाबले में ओन्स जबूर को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। एलेना रिबाकिना ने पहले सेट हारने के बाद शानदार वापसी की। उन्होंने ट्यूनीशिया की ओन्स जबूर को 3-6, 6-2, 6-2 से हराया। इसके साथ ही वह ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियनशिप जीतने वाले कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी बन गईं। 23 वर्षीय रिबाकिना का जन्म रूस के मॉस्को में हुआ था और वह 2018 से कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही है।

विंबलडन के दौरान ऑल इंग्लैंड क्लब ने यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस या बेलारूस का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में प्रवेश करने से रोक दिया था। 1962 के बाद ऑल इंग्लैंड क्लब में दो खिलाड़ियों के बीच यह पहला महिला खिताबी मैच था, जो पहली बार फाइनल खेल रही थीं। रिबाकिना इससे पहले किसी ग्रैंड स्लैम के सिंगल्स में सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच थीं। वहीं जबूर

रिबाकिना की अभी रैंकिंग में दुनिया की नंबर-23 खिलाड़ी हैं। 1975 में डब्ल्यूटीए रैंकिंग शुरू होने के बाद से रिबाकिना से कम रैंक वाली सिर्फ एक महिला ने विंबलडन जीता था। वह थीं वीनस विलियम्स। उन्होंने 2007 में नंबर 31 पर रहते हुए खिताब अपने नाम किया था। हालांकि, वह पहले नंबर वन रह चुकी थीं। इससे पहले वह 2019 में बुकारेस्ट और 2020 में होबार्ट ओपन का खिताब जीत चुकी हैं।

धोनी ने इंग्लैंड में की भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात

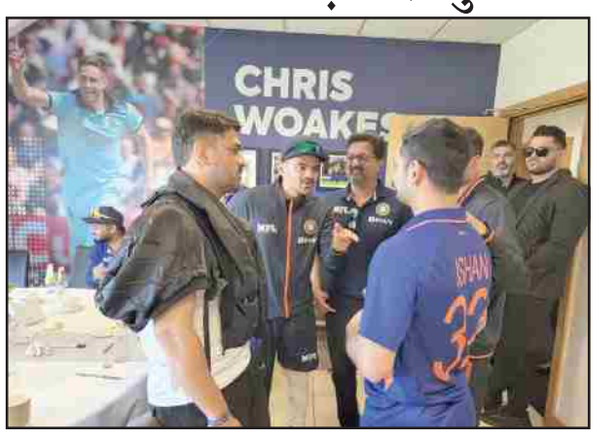

बर्मिंघम, 09 जुलाई (एजेन्सी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस समय इंग्लैंड में हैं। धोनी अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ इंग्लैंड इसलिए पहुंचे थे, क्योंकि वे अपनी मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे मनाना चाहते थे। हालांकि, एमएस धोनी हर दिन कहीं न कहीं अलग जगह पर देखा जा रहा है। ऐसा ही शनिवार 9 जुलाई को देखा गया, जब पूर्व महान विकेटकीपर बल्लेबाज बर्मिंघम पहुंचे और भारतीय खिलाड़ियों से मिले।

बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच को भारत ने अच्छे अंदाज में जीता और मैच खत्म होने के बाद एमएस धोनी ने भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। धोनी ने विकेटकीपर ऋषभ पंत और ईशान किशन के साथ लंबी बातचीत की। बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए फोटोज में पता चलता है कि ईशान ने कुछ टिप्स उनसे लिए।

बता दें कि धोनी ने 2019 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था और 2020 में संन्यास की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से वे टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आईपीएल में नजर आते हैं और खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव बांटते हैं।

इसके अलावा भारत के युवा खिलाड़ियों को जैसे ही धोनी के साथ बात या मुलाकात करने का मौका मिलता है तो वे उनसे कुछ न कुछ सीखना पसंद करते हैं।

सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच की धमाकेदार जीत

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। सर्बिया के दिग्गज टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विम्बलडन चैंपियनशिप 2022 मेंस सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना निक किर्गियोस के साथ होगा। जोकोविज ने सेमीफाइनल मैच में ब्रिटेन के कैरन नोरी को 2-6, 6-3, 6-2, और 6-4 से हराया। विम्बलडन चैम्पियनशिप का यह फाइनल मैच 10 जुलाई को खेला जाएगा।

मैच में कैरन नोरी ने जोकोविच के खिलाफ शानदार शुरुआत की थी और पहले सेट को अपने नाम किया था लेकिन टेनिस की दुनिया की में जोकर के नाम से मशहूर जोकोविच ने नवें सीड के कैमरन को लय में नहीं आने दिया। जोकोविच ने इसके बाद लगातार तीन सेट में जीत दर्ज करते हुए फाइनल में अपनी जगह को पक्का कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मैच ढाई घंटे तक चला।

विम्बलडन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में जब जोकोविच टेनिस कोर्ट में उतरेंगे तो उनकी नजर महान रोजर फेडरर को पीछे छोड़ने पर होगी। जोकोविच अब तक अपने करियर में 20 सिंगल्स स्लैम टाइटल अपने नाम किया है। ऐसे में रविवार को खेले जाने वाले फाइनल में अगर जोकोविच जीत दर्ज करते हैं वह इस मामले में फेडरर को पीछे छोड़ देंगे। वहीं सबसे अधिक सिंगल्स स्लैम टाइटल का खिताब राफेल नडाल के नाम है। नडाल ने 22 बार सिंगल्स स्लैम जीता है। नडाल विम्बलडन चैंपियनशिप 2022 में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे लेकिन चोटिल होने के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

वहीं सेमीफाइनल में नडाल के हटाने से निक किर्गियोस को वाकओवर मिला। किर्गियोस ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। वहीं जोकोविच ने आठवीं बार फाइनल तक सफर तय किया है।

रोहित ने विराट को पछाड़कर हासिल की अनोखी उपलब्धि, टी20 में लगाया चौकों का 'तिहरा शतक'

बर्मिंघम, 09 जुलाई (एजेन्सी)। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। हिटमैन के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 300 चौके पूरे हो गए हैं और वह यह कारनामा करने वाले दुनिया के दूसरे तथा भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित से पहले आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। भारतीय कप्तान ने शनिवार को एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान दूसरा चौके लगाते ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 चौके पूरे कर लिए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 20 गेंदों का सामना किया, जिसमें तीन चौके और दो छक्के लगाए। सलामी बल्लेबाज ने 31 रनों की पारी खेली।

संयोग से पूर्व कप्तान विराट कोहली भी उसी रिकॉर्ड का पीछा कर रहे थे। लेकिन वह मुकाबले में केवल एक ही रन बना पाए और इस रिकॉर्ड को कायम करने से चूक गए। कोहली के भी इस समय टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 298 चौके हैं।

कोहली पहले मैच का हिस्सा नहीं थे। लेकिन लगभग पांच महीने बाद उन्होंने टी20 टीम में वापसी की। विराट कोहली के लिए इस मैच में रन बनाना काफी जरूरी था क्योंकि वह काफी लंबे समय बाद वापसी कर रहे थे और अपनी जगह बनाए रखने के लिए उन्हें बड़े स्कोर बनाने की जरूरत थी। कोहली और रोहित दोनों को 34 साल की उम्र में अपना डेब्यू कर रहे रिचर्ड ग्लीसन ने आउट किया।

भारत ने लगातार दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड को 49 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत की इंग्लैंड के खिलाफ यह लगातार चौथी टी20 सीरीज जीत है। शनिवार को एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टी20 में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेट पर 170 रन का स्कोर बनाया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 17 ओवर में रन 121 पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के लिए मोईन अली ने सर्वाधिक 35 और डेविड विली ने नाबाद 33 रन बनाए। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने तीन जबकि जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।

इंग्लैंड में चला भुवनेश्वर कुमार की स्विंग का जादू

बर्मिंघम, 09 जुलाई (एजेन्सी)। भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 14 मैच में सिर्फ 12 विकेट लिये। पर्पल कैप की रेस में भुवी 27वें नंबर पर रहे। शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, उमेश यादव समेत कई ऐसे भारतीय गेंदबाजों के उनसे ज्यादा विकेट थे, जो टीम में नियमित नहीं है। यही वजह रही कि उनके टीम में होने पर सवाल उठने लगे। फिर दक्षिण अफ्रीका सीरीज में भुवनेश्वर कुमार पहले मैच में कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद भुवनेश्वर रुकने का नाम नहीं ले रहे।

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 32 भुवनेश्वर कुमार के कमाल से भारतीय टीम को जीत मिली। भारत ने 170 रन बनाए और लगा कि इंग्लैंड की खुंखार बल्लेबाजी के सामने यह स्कोर छोटा पर जाएगा। लेकिन भुवी के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने पहली गेंद आउट स्विंग डाली और जेसन रॉय के बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। अपने दूसरे ओवर में भुवी ने एक बार फिर शिकार किया। इस बार उनके निशाने पर थे जोस बटलर।

आईपीएल में गेंदबाजों की कुटाई करने वाले बटलर लगातार दूसरे मैच में भुवी की जाल में फंस गए। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने उनका कैच लिया। भुवी ने विकेटकीपर को आगे रखा था, जिससे बटलर क्रीज से बाहर नहीं निकले और टीम को फायदा मिला। अपने तीसरे ओवर में भुवी ने निचले क्रम के बल्ले रिचर्ड ग्लीसन को आउट किया। 3 ओवर के स्पेल में उन्होंने 15 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

आईपीएल के बात भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 9 टी20 मैच खेले हैं, जिसकी 8 पारियों में उन्होंने गेंदबाज की। इस दौरान भुवी ने 14.33 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 मुकाबलों में 6 से कम की इकोनॉमी से रन खर्च किए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के कटक टी20 में 13 रन देकर 4 विकेट लिए थे। वहीं अन्य गेंदबाज विकेट के लिए जूझ रहे थे। एक समय टीम से बाहर होने की कगार पर खड़े भुवनेश्वर कुमार ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए बड़ी दावेदारी पेश कर दी है।

भारत के पास राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने का अच्छा मौका : मिताली राज

कोलकाता, 09 जुलाई (एजेन्सी)। पूर्व कप्तान मिताली राज का मानना है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पास आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने का अच्छा मौका है लेकिन इसके लिए उसे सही रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा।

कुआलालंपुर में 1998 के सत्र में पुरुषों के टूर्नामेंट के आयोजन के बाद पहली बार महिला क्रिकेट को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है।

भारत ग्रुप ए में है और वह 29 जुलाई को अपने शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। पाकिस्तान और बारबाडोस ग्रुप की अन्य दो टीमें हैं।

मिताली ने यहां अपनी जिंदगी पर बनी फिल्म शाबाश मिठू के प्रमोशन के मौके पर कहा, मुझे लगता है कि किसी भी बड़े आयोजन से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी तैयारी और सही रणनीति के साथ मैदान पर उतरते है तो पदक जीतने का अच्छा मौका होगा।

इस पूर्व कप्तान ने यहां ईडन गार्डेन्स में कहा कि पंजाब की हरफनमौला हरमनप्रीत के पास इतना अनुभव है कि वह इन खेलों में भारत को शीर्ष पर पहुंचा सकें।

इस 39 साल की पूर्व खिलाड़ी ने कहा, वह (हरमनप्रीत) 2016 से टी20 टीम का नेतृत्व कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि उसके पास राष्ट्रमंडल खेलों में टीम का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त अनुभव है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से आठ अगस्त तक होगा। क्रिकेट मैच का सेमीफाइनल छह अगस्त और फाइनल सात अगस्त को खेला जायेगा।

निर्वाचित होने पर जम्मू कश्मीर में शांति, न्याय, लोकतंत्र की बहाली मेरी प्राथमिकता : यशवंत सिन्हा

श्रीनगर, 09 जुलाई (एजेन्सी)। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शनिवार को कहा कि अगर वह निर्वाचित होते हैं तो उनकी प्राथमिकताओं में कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान और केंद्र शासित प्रदेश में शांति, न्याय, लोकतंत्र तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार से आग्रह करना शामिल रहेगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व नेता सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में अभी कोई विधानसभा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश से पांच लोकसभा सदस्य हैं, इनमें तीन नेशनल कॉन्फ्रेंस से और दो भाजपा से हैं। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं हैं।

सिन्हा ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'अगर निर्वाचित होता हूं तो मैं बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मेरी प्राथमिकताओं में कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने और शांति, न्याय, लोकतंत्र, सामान्य स्थिति बहाल करने तथा जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का सरकार से आग्रह करना शामिल रहेगा।'

उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में सद्भाव नष्ट हो गया है, लेकिन राष्ट्र वापस लड़ेगा क्योंकि उसका मिजाज सांप्रदायिकता के खिलाफ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बेहद खेदजनक है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के लगभग तीन साल बाद भी उच्चतम न्यायालय ने इससे संबंधित मामले की सुनवाई शुरू नहीं की है।

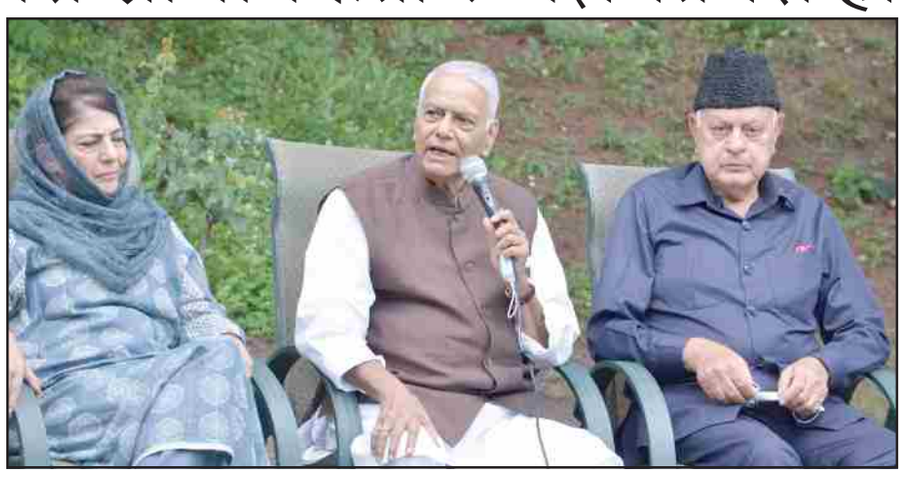

उन्होंने कहा, 'संवैधानिक मामले लंबित रहने से शीर्ष अदालत की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है।' साथ ही, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए तथा विधानसभा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए।' उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर में जबरन और हेरफेर करने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तन का विरोध करता हूं।'

सिन्हा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास के लिए स्थितियां बनाने के अपने वादे में विफल रही है। उन्होंने कहा,' न केवल कश्मीरी पंडितों के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी वादा पूरा करना चाहिए, जिन्हें कश्मीर से पलायन करने करने के लिए मजबूर किया गया था।'

सिन्हा ने कहा,' 2020 में एक सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'दिल की दूरी' और 'दिल्ली की दूरी' को खत्म करने का वादा किया था। दो साल से अधिक समय बीत चुका है, वादा अधूरा है।'

सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर उनके मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने कहा, 'हांलाकि, मैं उनसे वही प्रतिज्ञा और वादे करने का आग्रह करता हूं जो मैंने किए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी उनसे इस आश्वासन की उम्मीद करते हैं।'

सिन्हा ने कहा कि उनसे उनकी श्रीनगर यात्रा का कारण पूछा गया क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जम्मू कश्मीर का बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व नहीं है। सिन्हा ने कहा,'मैने उनसे कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुए अन्याय को उजागर करने के लिए श्रीनगर जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि शेष भारत के लोग यह जानें कि कैसे जम्मू कश्मीर में उनके हमवतन लोगों से उनके मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं।'

एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 'प्रबंधन' के जरिए नहीं जीता जा सकता है। सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में हुए अन्याय से लडने की कोई इच्छाशक्ति नहीं है। शायद, इसलिए विधानसभा चुनाव नहीं कराया गया है। शायद इसलिए अनावश्यक परिसीमन कवायद की गई जिसने किसी के साथ न्याय नहीं किया। उन्हें पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को प्रबंधन से नहीं जीता जा सकता।'

देश के हालात के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने कहा, ' देश में स्थिति खराब हो गई है। सद्भाव खत्म हो गया है। अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में सबको पता है।' उन्होंने कहा, च्चराष्ट्र का अपना स्वभाव होता है। वर्तमान स्थिति एक भटकाव है। अगर हम सब इसके खिलाफ मिलकर काम करते हैं, तो इस स्थिति से बच सकते हैं।'

विकास के लिए सरकार बनाई : शिंदे

फडणवीस का दावा- कार्यकाल पूरा करेंगे

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में हैं। वे शुक्रवार रात दिल्ली पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वे आज ही पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं ने दिल्ली में एक साझा प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाजपा और शिवसेना का स्वाभाविक गठबंधन ही महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है।

एकनाथ शिंदे ने कहा कि एमवीए सरकार के तहत हमारे विधायकों का अस्तित्व खतरे में आ गया था, तब हम बोल नहीं सकते थे इसलिए हमने यह कदम उठाया। भाजपा और शिवसेना का स्वाभाविक गठबंधन ही महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है।

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि विकास की भूमिका लेकर हमने ये सरकार बनाई है। जो काम 2.5 साल पहले होना था वो अब हुआ है। आज हम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका विजन जानेंगे। उन्होंने शपथ के वक्त कहा था कि महाराष्ट्र को कोई भी कमी नहीं होगी।

वहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे पहले सीएम बनाया, अब पार्टी की जरूरत के हिसाब से हमने पार्टी के फैसले का पालन किया है। एकनाथ शिंदे हमारे नेता और सीएम हैं। हम उसके अधीन काम करेंगे। अब हमारा प्राकृतिक गठबंधन पुनर्जीवित हो गया है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के साथ काम करेंगे और इस सरकार को सफल बनाना हमारी प्राथमिकता है।

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अमरावती जिले के पचडोंगरी और कोयलरी गांवों में कुएं से दूषित पानी पीने की वजह से मारे गए लोगों के परिवारों को सीएम सहायता कोष से 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की। सीएमओ के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अमरावती जिले में दूषित पानी पीने के बाद बीमार होने वालों को सरकारी खर्च पर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं।

इससे पहले दोनों नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में भारी सियासी उठापटक व शिवसेना में बगावत के बाद शिंदे और फडणवीस ने 30 जून को राज्य में सत्ता की बागडोर संभाली थी। इसके पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र के दोनों नेताओं ने शुक्रवार रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के बागी गुट के बीच सत्ता साझेदारी के फार्मूले पर चर्चा की। शाह ने शुक्रवार रात ट्वीट कर कहा- 'मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप दोनों ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे और महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।'

पुणे से शिवसेना के पूर्व पार्षद प्रमोद भंगीरे और उनके सहयोगियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दिया है। मोहम्मदवाड़ी-हडपसर क्षेत्र में वार्ड संख्या 46 का प्रतिनिधित्व करने वाले भंगीरे शिंदे गुट के लिए समर्थन व्यक्त करने वाले पुणे के पहले पूर्व पार्षद हैं। गौरतलब है कि पुणे के कई शिवसेना पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिंदे के संपर्क में हैं और उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं।

देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के अंडरवर्ल्ड से जुड़े तार, जांच के घेरे में छोटा शकील

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) द्वारा कथित तौर पर किए गए देश के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी घोटाले के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस संबंध में पाकिस्तान स्थित अपराधी छोटा शकील के साथ कुछ संदिग्धों की जांच कर रही है।

जांच अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि जनता के पैसे को कथित रूप से शकील से जुड़े लोगों को भेजा गया था। अधिकारियों ने कहा कि इस पहलू की आगे जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीएचएफएल घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने शुक्रवार को मुंबई और पुणे में तीन स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने यहां से 40 करोड़ रुपये से अधिक की पेंटिंग और मूर्तियां बरामद कीं।

बीआई को मुंबई में अजय रमेश नवनदार के ठिकानों पर छापे में करोड़ों की विदेशी घड़ियां मिलीं। वहीं, रेबेका दीवान के खार पश्चिम के फ्लैट में तलाशी अभियान चलाया गया। समझा जाता है कि यह डीएचएफएल के कपिल वधावन से लिया गया था।

सीबीआई ने अपने बयान में कहा है, जांच के दौरान यह पाया गया कि डीएचएफएल के प्रवर्तकों ने कथित तौर पर फंड को डायवर्ट किया और विभिन्न जगहों पर उसका निवेश किया। उस फंड से उन्होंने महंगी पेंटिंग और मूर्तियां भी खरीदी, जिसकी कीमत करीब 55 करोड़ रुपये हैं।

गौरतलब है कि सीबीआई 34,615 करोड़ के घोटाले में डीएचएफएल, उसके पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के चेन्नई स्थिति आवास पर सीबीआई का छापा

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चीनी वीजा मामले में शनिवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के चेन्नई स्थित आवास की तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 17 मई को तलाशी के दौरान कार्ति चिदंबरम के घर के एक हिस्से को सील कर दिया गया था, क्योंकि उस हिस्से की चाबियां उपलब्ध नहीं थीं।

उन्होंने बताया कि यह बताया गया था कि चाबियां उनकी पत्नी के पास है, जो तलाशी के समय विदेश में थीं। उन्होंने बताया कि एजेंसी को चाबियां मिलने के बाद शनिवार को उस हिस्से में तलाशी फिर से शुरू की गई। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को की गई तलाशी को 17 मई को हुई तलाशी अभियान का हिस्सा माना जाएगा। कार्ति ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।

सीबीआई ने उनके और अन्य के खिलाफ वेदांता समूह की कंपनी 'तलवंडी साबो पावर लिमिटेड' (टीएसपीएल) के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा उन्हें और उनके करीबी सहयोगी एस भास्कर रमन को 50 लाख रुपये की रिश्वत देने के आरोप में 14 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी।

कार्ति चिदंबरम पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल के दौरान 'तलवंडी साबो पावर लिमिटेड' के लिए काम कर रहे चीन के 263 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। टीएसपीएल पंजाब में एक बिजली संयंत्र स्थापित कर रही थी। उस समय पी.चिदंबरम गृह मंत्री थे।

ई-फार्मेसी और चिकित्सा उपकरणों पर नियंत्रण के लिए नए विधेयक की तैयारी

नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेन्सी)। सरकार ने पहली बार ई-फार्मेसियों और चिकित्सा उपकरणों को नियंत्रित करने वाले एक नए विधेयक का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा नए विधेयक के इस प्रस्ताव में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों दोनों के क्लीनिकल ट्रायल के दौरान चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहने के लिए कारावास और दंड का प्रावधान किया गया है।

इस प्रस्ताव में नई दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के क्लीनिकल ट्रायल के संचालन के लिए नियमों को, नई दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2022 के मसौदे के तहत लाया गया है, जो 1945 के मौजूदा ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है। इस मसौदा विधेयक को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसे लेकर जनता और हितधारकों से सुझाव, टिप्पणियां और आपत्तियां 45 दिनों के भीतर मांगी हैं।

मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की समीक्षा और उसमें संशोधन के लिए विचार-विमर्श 2016 से जोर-शोर से शुरू किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिशों और व्यापक कानून की आवश्यकता को देखते हुए नई औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरण विधेयक तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

समिति की सिफारिशों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2022 के मसौदे का प्रस्ताव किया है ताकि बदलती जरूरतों, समय और प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाया जा सके।

इस मसौदा विधेयक में एक अलग औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) और चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड (एमडीटीएबी) के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें तकनीकी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए विभिन्न संघों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

18 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही होगा। इस सत्र में भी सांसद सामाजिक दूरी और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। यह बात राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नए सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद कही।

देशभर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए संसद के मानसून सत्र में भी कोविड-19 प्रतिबंध लागू रहेंगे। पिछले कुछ सत्र भी इन पाबंदियों के तहत ही हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बीच व्यापक चर्चा के बाद लिया गया है। यह भी ध्यान में लाया गया कि संसद के 80 फीसदी सदस्य और सचिवालय के स्टाफ कोरोना की बूस्टर खुराक समेत टीका लगवाने में सक्षम हैं। साथ ही सांसदों से यह भी उम्मीद होगी कि वे हर समय मास्क लगाए रहेंगे और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करेंगे।

अगर मेरी सरकार गिरी तो कल्याणकारी योजनाएं रुक जाएंगी: जगन मोहन रेड्डी

अमरावती, 09 जुलाई (एजेन्सी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर वर्ष 2024 के आम चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस की हार होती है, तो उनकी सरकार द्वारा शुरू की गईं मुफ्त सेवाएं देने वाली सभी योजनाएं भी बाधित हो जाएंगी।

रेड्डी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस बारे में लोगों को सतर्क करने को कहा। वाईएसआर कांग्रेस के दो दिवसीय आम सम्मेलन में समापन भाषण देते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पीत मीडिया'' ने संकेत देना शुरू कर दिया है कि अगर उनकी सरकार गिरी तो करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं बंद कर दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, (तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख) चंद्रबाबू नायडू के पक्ष में मतदान कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ मतदान होगा। लोगों को चंद्रबाबू को हराने के लिए अर्जुन की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि वह साइकिल (तेदेपा का चुनाव चिह्न) चलाने में सक्षम नहीं हैं।''

उन्होंने लोगों से नायडू और तीन तेलुगु मीडिया घरानों की दुष्ट चतुस्थात्माओं (चार दुरात्माओं)'' से दूर रहने की अपील की। रेड्डी ने आरोप लगाया, चंद्रबाबू आपके पास सभी तरह के झूठे वादों के साथ आएंगे।

चार दुरात्माएं हमारी सरकार द्वारा लागू कल्याणकारी योजनाओं को रोकना चाहती हैं।''

सीएम शिंदे ने पीएम मोदी से मुलाकात की

राजेश अलख

नई दिल्ली, 09 जुलाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री के साथ पहली बैठक है। शिंदे और फडणवीस ने प्रधानमंत्री से उनके लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में मुलाकात की और महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन'' मांगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।'' इससे पहले शिंदे ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वह राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को समझने और महाराष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करेंगे।

शिंदे ने कहा कि मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाले समृद्धि एक्सप्रेस वे, शहरों में मेट्रो टेन और सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए खेतों में तालाब बनाने जैसी उन कई परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जाएगा, जो फडणवीस ने शुरू की थीं, लेकिन उद्धव ठाकरे नीत सरकार के कार्यकाल में इनमें देरी हुई। ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री और फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी।

लोगों को बांटने का हथियार नहीं हो सकता धर्म : सीएम स्टालिन

चेन्नई, 09 जुलाई (एजेन्सी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने शनिवार को कहा कि धर्म लोगों को बांटने का हथियार नहीं हो सकता और जो लोग इस तरह के विभाजन का कारण बनते हैं, वे सच्चे अध्यात्मवादी नहीं हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को मंदिरों के जीर्णोद्धार और विरासत वाले शहरों में बुनियादी ढांचे में सुधार सहित विकास के लिए द्रमुक के योगदान के बारे में पता नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वालों का विरोध करते हैं। स्टालिन ने कहा कि वह उन लोगों की उपेक्षा करते हैं जो उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप सस्ते प्रचार की कोशिश कर रहे लोगों के हैं।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने 340 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कहा, मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है जो झूठ बोलते हैं और सस्ता प्रचार चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि वह धर्म के आधार पर डीएमके पार्टी या सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से चला रहे हैं।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रक: नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com